दैनिक दिव्य संवाद

RNI No. MPHIN/25/A4421

मौसम आज
तापमान
न्यूनतम - 26 डि.से.
अधिकतम - 38 डि.से.

वर्ष 01 अंक: 131 | उज्जैन बुधवार दिनांक 17 जून 2026 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय संवत् 2083 | पृष्ठ: 8 मूल्य : 02 रूपये

न्यूज गैलरी

घर खरीदारों से धोखाधड़ी में रहेजा डेवलपर्स की 503 करोड़ की संपत्तियां अटैच

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईडी ने रहेजा डेवलपर्स और इसके प्रमोटर नवीन एम रहेजा के खिलाफ घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के संबंध में मनी लांड्रिंग जांच के तहत लगभग 503 करोड़ रुपये की नई संपत्तियों को अटैच किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लांड्रिंग मामले में पीएमएलए के तहत एक अस्थायी अटैचमेंट आदेश जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा कि आदेश के तहत रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड की संपत्तियों को अटैच किया गया है, जिनकी वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 503.48 करोड़ रुपये है। साथ ही नवीन एम. रहेजा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रखी गई संपत्तियां भी शामिल हैं। यह जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई कई एफआइआर से शुरू हुई है, जो कंपनी द्वारा लांच किए गए विभिन्न आवासीय परियोजनाओं के संबंध में बड़ी संख्या में घर खरीदारों द्वारा की गई शिकायतों पर आधारित है। ईडी के अनुसार, इसकी जांच में पाया गया कि रहेजा डेवलपर्स ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए लगभग 4,600 घर खरीदारों से 2,425.99 करोड़ रुपये जुटाए।

बिना लोकसभा चुनाव लड़े ही 20 सांसदों वाली पार्टी बनेगी NCPI, TMC के बागियों ने बनाया नया ठिकाना

नई दिल्ली (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी लोकसभा सदस्यों द्वारा विलय की घोषणा से पहले नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी आफ इंडिया (एनसीपीआई) का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। लेकिन, तृणमूल के बागी सांसदों ने जबसे एनसीपीआई का दामन थामा है, उसके बाद से यह कम जानी-पहचानी पार्टी अचानक राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गई है।

लोकसभा चुनाव लड़े बिना यह 20 सांसदों वाली पार्टी बन जाएगी। अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस विलय को मंजूरी दे देते हैं, तो एनसीपीआई लोकसभा में छठी सबसे बड़ी पार्टी होगी। सत्तारूढ़ राजग में यह भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, जो तेदेपा (16 सांसद) और जदयू (12 सांसद) से काफी आगे होगी।

यह अलग बात है कि इस पार्टी के पास वर्तमान में सांसद या विधायक तो दूर, कोई स्थानीय निकाय पार्षद तक नहीं है। वित्त वर्ष 2022-23 के आखिर में एनसीपीआई के पास कैश के तौर पर सिर्फ 75 रुपये बचे थे। यह जानकारी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को सौंपी गई सालाना आडिट रिपोर्ट में सामने आई है।

कभी दिया था दलबदलुओं को नकारें का नारा इसे एक राजनीतिक विडंबना ही कहेंगे कि तीन साल पहले जिस पार्टी ने दलबदलुओं को नकारें का नारा दिया था, आज वही तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं का स्वागत कर रही है। इस दल ने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीतिक दल-बदलुओं को नकारें के नारे के साथ चार उम्मीदवार उतारे थे।

बेहतर प्रबंधन और कुशलता से करायें नीट की परीक्षा, कहीं भी न रहे कोई कमी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। इसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। बेहतर प्रबंधन एवं कार्य कुशलता से पूरी पारदर्शिता के साथ यह परीक्षा सम्पन्न करायें। उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में नीट (अंडर ग्रेजुएट) परीक्षा-2026 की आगामी रविवार (21 जून) को होने वाली परीक्षा की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। यह परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों में सम्पन्न कराई जाएगी। नीट परीक्षा की कुल अवधि सवा तीन घंटे की होगी। इस बार सभी परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नीट परीक्षा के समन्वयक उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी परीक्षा केन्द्रों में लगाई जाने वाली बायोमैट्रिक मशीन, सीसीटीवी कैमरे एवं जैमर 19 जून को ही परीक्षा केन्द्रों में लगा दिए जाएं और 20 जून को इनका ट्रायल रन भी कर लिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 21 जून को राष्ट्रपति महोदया का जबलपुर प्रवास प्रस्तावित है। जबलपुर शहर में 24 केंद्रों में नीट परीक्षा होनी है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी यातायात का ऐसा प्रबंधन करें कि सभी परीक्षार्थी बिना किसी बाधा के अपने-अपने परीक्षा केंद्रों में सुगमता से पहुंच जायें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चूंकि नीट परीक्षा के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में भी होने हैं, इन आयोजनों के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई कठिनाई न हो। यातायात का बेहतर नियोजन करें। सुनिश्चित करें कि सभी परीक्षार्थी तय समय से पहले तक केन्द्रों में पहुंच जायें। किसी परीक्षार्थी को यदि सेंटर तक पहुंचने में आवागमन के साधन की परेशानी आ रही है तो प्रशासन और पुलिस अधिकारी किसी शासकीय वाहन या खुद अपने वाहन से उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परीक्षा केंद्रों वाले सभी 30 जिलों के कलेक्टर्स-एसपी एवं परीक्षा सम्पन्न कराने की व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों को वीसी से निर्देशित किया कि नीट परीक्षा की तैयारियों के लिए उपयोग में लाई गई एसओपी अब प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं में उपयोग में लाई जाएगी। परीक्षा केन्द्रों वाले जिलों के पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य संबंधित अधिकारियों ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़कर परीक्षा की अब तक की तैयारियों की जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा एवं जनसंपर्क श्री अनुपम राजन ने परीक्षा की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि नीट परीक्षा आयोजन के लिए जिलास्तरीय समन्वय समिति का गठन कर इनकी बैठकें भी कर ली गई है। नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर जिला नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है। प्रत्येक 3-4 परीक्षा केन्द्रों के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सहायक उपनिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

अपर मुख्य सचिव श्री राजन ने बताया कि नीट परीक्षा आयोजन के लिए संबंधित जिलों में सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किये गये है। परीक्षा के प्रश्नपत्र प्रदेश के 5 एयरपोर्ट के जरिए पहुंच चुके है। प्रश्न पत्र एनटीए द्वारा तय किये गये 2 अधिसूचित बैंकों में सुरक्षित रखे गये हैं। परीक्षा के दिन वाहनों की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। इन वाहनों की जानकारी शाम तक एनटीए को दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में द्वि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। बाहरी सुरक्षा परत राज्य पुलिस / होमगार्ड की होगी। आंतरिक सुरक्षा परत एनटीए द्वारा नियुक्त एजेंसी की रहेगी। महिला विद्यार्थियों के लिए अलग से फ्रिस्किंग सुविधा रहेगी। इसके लिए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जनरेटर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। परीक्षा कक्ष में उचित प्रकाश व्यवस्था तथा पंखे चालू अवस्था में हों, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

आधार के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, पहचान पत्र तक सीमित करने की मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल नागरिकता, मूल निवास और आवासीय पते के सुबूत के तौर पर गलत तरीके से किया जा रहा है। इसमें केंद्र, राज्यों और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि आधार का उपयोग सिर्फ पहचान की पुष्टि तक सीमित किया जाए।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की पीठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकती है।

वकील अश्वनी दुबे के जरिये दायर याचिका में यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि नए मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र में जन्म तिथि और निवास के सुबूत के तौर पर आधार का इस्तेमाल आधार एक्ट, 2016 की धारा नौ; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) और संविधान के अनुच्छेद-14 के विरुद्ध माना जाए।

भारत आ रहे LNG जहाज ने पार किया होर्मुज, फंसे हुए 34 अन्य जहाजों के लिए जगी उम्मीद

नई दिल्ली (एजेंसी)। सोमवार को भारत आ रहे एलएनजी वाहक जहाज दिशा के होर्मुज से सुरक्षित गुजरने के बाद फारस की खाड़ी में फंसे 34 अन्य भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों तक सुरक्षित और तेजी से पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। यह राहत ऐसे समय में मिली है जब अमेरिका और ईरान ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के फैसले की घोषणा की है।

जहां उर्वरक से लदे 16 जहाजों की संभावित रवानगी से कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी, वहीं नीति निर्माता अभी भी आशंकित हैं। उन्हें चिंता है कि ऊर्जा आपूर्ति में सुधार से तत्काल राहत नहीं मिल सकती है, क्योंकि कतर के रास लाफान जैसे केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा है।

बेहतर ऊर्जा आपूर्ति से तत्काल राहत शायद ही मिले क्योंकि गैस प्लांट और अन्य सुविधाओं को हुए व्यापक नुकसान से यह अनिश्चितता पैदा हो गई है कि सामान्य परिचालन कब शुरू होगा।

अल नीनो के प्रभाव से भारत में कमजोर पड़ सकता है मानसून, यूएन ने दी चेतावनी

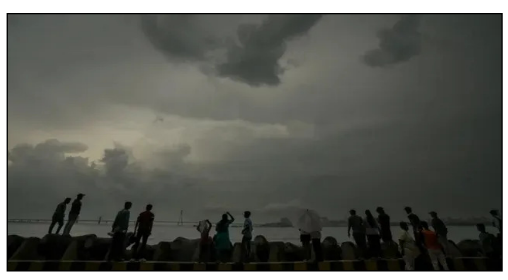

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रशांत महासागर में विकसित होने वाली जलवायु संबंधी घटना अल नीनो का नया दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने चेतावनी दी है कि इसका भारत सहित एशिया के कई देशों की कृषि और खाद्य सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

विशेष रूप से भारत में मानसून कमजोर पड़ने की आशंका जताई गई है, जिससे धान और मक्का जैसी वर्षा आधारित खरीफ फसलों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है।

एफएओ के अनुसार, अल नीनो के प्रभाव से भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। इससे खेती के लिए आवश्यक नमी में कमी आएगी और फसलों की वृद्धि के महत्वपूर्ण चरणों में उत्पादन पर दबाव बढ़ेगा। धान और मक्का जैसी फसलें मुख्य रूप से मानसूनी बारिश पर निर्भर होती हैं, इसलिए इनके उत्पादन में गिरावट की आशंका बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अल नीनो का प्रभाव केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर वैश्विक खाद्य बाजारों और कीमतों पर भी पड़ सकता है। उत्पादन में कमी आने से खाद्यान्न आपूर्ति प्रभावित होगी और कई देशों को आयात पर अधिक निर्भर होना पड़ सकता है। भारत सहित इन देशों में सूखे का खतराएफएओ का विश्लेषण पिछले 41 वर्षों की उपग्रह तस्वीरों और जलवायु आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और तिमोर-लेस्ते जैसे देशों में सूखे का खतरा बढ़ सकता है।

इन क्षेत्रों में कृषि पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका है। रिपोर्ट में 2015-16 के अल नीनो का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि उस दौरान भारत में मक्का उत्पादन में चार प्रतिशत और धान उत्पादन में एक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी।

मेफेड्रोन बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल रेगुलेशन के दायरे में

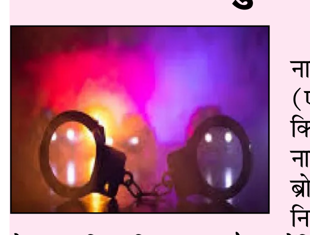

नई दिल्ली (एजेंसी)। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सोमवार को बताया कि केंद्र सरकार ने एंटी-नारकोटिक्स कानून के तहत 2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन को नियंत्रित पदार्थ घोषित किया है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि इस केमिकल का इस्तेमाल मेफेड्रोन नामक नशीला पदार्थ बनाने में बढ़ रहा है। अब इस केमिकल के इस्तेमाल पर नजर रखी जाएगी। एनसीबी ने कहा कि वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व विभाग ने 11 मार्च को इस सिलसिले में अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत 2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन के निर्माण, वितरण, बिक्री, खरीद, भंडारण, इस्तेमाल, आयात-निर्यात या किसी वेबसाइट, इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से इसकी खरीद-बिक्री कराने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को एनसीबी से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी है।

TMC सांसद कल्याण बनर्जी को संसद से निकालने की मांग, बागी MP काकोली घोष ने स्पीकर को लिखा पत्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अपने ही साथी सांसद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर निकालने की मांग की है।

उन्होंने बनर्जी पर संसद के अंदर बार-बार अपशब्द कहने, महिलाओं के प्रति अपमानजनक बातें करने और गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

यह शिकायत घोष दस्तीदार और 19 अन्य सांसदों द्वारा नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय की घोषणा करने के एक दिन बाद आई है, जिससे तृणमूल कांग्रेस में फूट और गहरी हो गई है।

28 मई की पिछली शिकायत के बाद लिखे गए एक पत्र में, बारासात की सांसद ने आरोप लगाया कि बनर्जी ने संसदीय कार्यवाही के दौरान उनके और अन्य महिला सांसदों के खिलाफ बार-बार आपत्तिजनक, अपमानजनक और अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया।

उन्होंने लिखा, कई मौकों पर, कल्याण बनर्जी ने सदन की बैठकों और कार्यवाही के दौरान मेरे और अन्य महिला सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक, अपमानजनक और अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया है। ऐसा व्यवहार एक सांसद के लिए शोभा नहीं देता और यह चुने हुए प्रतिनिधियों से अपेक्षित संसदीय बहस की गरिमा, मर्यादा और मानकों को कम करता है। उनके पत्र के अनुसार, बनर्जी ने बार-बार उन पर व्यक्तिगत हमले, डराया-धमकाया और महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां कीं।

उन्होंने कहा, ऐसा व्यवहार मजबूत राजनीतिक असहमति या संसदीय बहस की सीमाओं से परे है और व्यक्तिगत दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के दायरे में आता है। इस व्यवहार से न केवल उन्हें व्यक्तिगत पीड़ा हुई है, बल्कि एक ऐसा माहौल भी बना है जो संसदीय कार्यवाही में महिलाओं की स्वतंत्र भागीदारी को हतोत्साहित करता है।

सांसद ने आगे कहा कि बनर्जी के कार्यों ने संसदीय मानदंडों और लोकसभा में प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के नियमों का उल्लंघन किया है। नियम 349 और 352 का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और संसदीय शिष्टाचार के मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

पत्र में कहा गया है, कल्याण बनर्जी का व्यवहार शिष्टता और आपसी सम्मान के उन मानकों की अनदेखी को दर्शाता है, जो एक विचार-विमर्श करने वाली संसदीय संस्था के कामकाज के लिए अपरिहार्य हैं।

सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर राम मंदिर चंदे में गड़बड़ी की जांच की मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन में अनियमितताओं और हेराफेरी के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र याचिका भेजी गई है। पत्र में मंदिर के दान को लेकर उठे सवालों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।

वकील अनूप प्रकाश अवस्थी द्वारा भेजी गई इस पत्र याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह मंदिर में प्राप्त दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे। साथ ही मामले की जांच सीबीआइ जैसी एजेंसी से कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग भी की गई है।

पत्र में कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां देश-विदेश से श्रद्धालु बड़ी मात्रा में दान और चढ़ावा अर्पित करते हैं। ऐसे में मंदिर के धन के संग्रह, लेखा-जोखा, संरक्षण और खर्च में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि मंदिर में दान प्रबंधन से जुड़े कुछ व्यक्तियों के पास उनकी ज्ञात आय से कहीं अधिक संपत्ति होने की खबरें सामने आई हैं। हालांकि, इन आरोपों की सत्यता की पुष्टि केवल सक्षम और स्वतंत्र जांच के माध्यम से ही हो सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इन आरोपों ने देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के बीच चिंता पैदा कर दी है।

सुरक्षा मानकों के क्रियान्वयन के लिए आईआईटी मुबंई के विशेषज्ञ 18 जून को देंगे प्रशिक्षण

सिंहस्थ 2028 के कार्यों में निर्माण सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

उज्जैन। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से सिंहस्थ मेला अधिकारी एवं जिला कलेक्टर द्वारा किए जा रहे नवाचारों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की जा रही है। सिंहस्थ से संबंधित विभिन्न निर्माण एवं अधोसंरचना कार्यों में सुरक्षा मानकों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विशेषज्ञ प्रोफेसरों द्वारा 18 जून को आयोजित किया जाएगा।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सिंहस्थ 2028 से संबंधित निर्माण कार्यों में संलग्न अधिकारियों एवं अभियंताओं को आधुनिक सुरक्षा मानकों, जोखिम प्रबंधन तथा निर्माण स्थलों पर अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम सुरक्षा प्रक्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षित करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक बैच में लगभग 40 अधिकारियों को शामिल किया जाएगा तथा कुल 6 बैचों में यह प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रथम प्रशिक्षण सत्र का आयोजन दिनांक 18 जून को प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में पांच तकनीकी सत्र आयोजित होंगे

प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल पांच तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। जिसमें प्रथम सत्र में Why safety system fail even when risks are ह्मठ्ठश्र2ठ्ठ विषय पर चर्चा की जाएगी, जिसमें ज्ञात जोखिमों के बावजूद सुरक्षा व्यवस्थाओं के विफल होने के कारणों का विश्लेषण किया जाएगा तथा उज्जैन एवं सिंहस्थ से संबंधित परिस्थितियों पर विशेष चर्चा होगी। द्वितीय सत्र में Discussion on safety hazards amd what safety codes say विषय के अंतर्गत विभिन्न सुरक्षा जोखिमों एवं उनसे संबंधित सुरक्षा संहिताओं और मानकों की जानकारी दी जाएगी। तृतीय सत्र में Quantifying safety and Discussing newest monitoring techniques विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें सुरक्षा के आकलन की आधुनिक पद्धतियों तथा नवीनतम मॉनिटरिंग तकनीकों से प्रतिभागियों को अवगत कराया जाएगा।

चतुर्थ सत्र में Development of a renewed safety management plan for their sites विषय पर चर्चा होगी, जिसके माध्यम से प्रतिभागी अपने-अपने कार्यस्थलों के लिए प्रभावी एवं अद्यतन सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण करना सीखेंगे। पंचम एवं अंतिम सत्र में Reviewing the safety management plan of a site along with the participants के अंतर्गत प्रतिभागियों द्वारा तैयार सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा एवं विश्लेषण किया जाएगा तथा विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक सुझाव प्रदान किए जाएंगे।

प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यस्थलों पर बेहतर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने में सक्षम होंगे यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सिंहस्थ 2028 से जुड़े निर्माण कार्यों में सुरक्षा संस्कृति को सुदृढ़ करने, दुर्घटनाओं की संभावनाओं को न्यूनतम करने तथा कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों एवं अभियंताओं में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तथा वे अपने कार्यस्थलों पर बेहतर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने में सक्षम होंगे। सिंहस्थ मेला प्रशासन का उद्देश्य सिंहस्थ 2028 के समस्त निर्माण एवं विकास कार्यों को सर्वोच्च सुरक्षा मानकों के अनुरूप पूर्ण कराना है, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।

मंगल 21 जून को करेगा वृषभ राशि में प्रवेश, शनि की दृष्टि से बाजार मौसम और वैश्विक राजनीति में मचेगी उथल-पुथल

उज्जैन। वर्ष 2026 के उत्तरार्ध की शुरुआत बड़े और संवेदनशील ज्योतिषीय बदलाव के साथ होने जा रही है। ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को मेष से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल देव इस राशि में 1 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। श्री मातंगी ज्योतिष केंद्र के प्रख्यात ज्योतिर्विद पं. अजय कृष्णशंकर व्यास के अनुसार वृषभ राशि में मंगल पर न्याय के देवता शनि देव की दृष्टि रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में शनि और मंगल के इस संबंध को बेहद प्रभावशाली माना गया है। इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, कृषि, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और आम जनजीवन पर दिखाई देगा।

बाजार में रहेगा भारी उतार-चढ़ाव

वृषभ राशि को धन और संसाधनों का भाव माना जाता है। श्री मातंगी ज्योतिष केंद्र के ज्योतिर्विद पं. अजय कृष्णशंकर व्यास ने बताया कि मंगल के इस गोचर पर शनि की दृष्टि वैश्विक स्तर पर आर्थिक दबाव बढ़ा सकती है। खाद्यान्न, सोना, चांदी, तांबा, क्रूड ऑयल और सीमेंट-सरिया के दामों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों को बाजार में सट्टेबाजी या जल्दबाजी में निवेश से बचना चाहिए। अल्पकालिक लाभ की जगह दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा।

मौसम का मिजाज बिगड़ेगा, कृषि क्षेत्र में बढ़ेगी चुनौती

वृषभ एक पृथ्वी तत्व की राशि है जिसका सीधा संबंध कृषि और प्रकृति से है। इस गोचर के प्रभाव से मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देश और दुनिया के कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश होगी, जबकि कुछ हिस्सों में सूखे या अतिवृष्टि जैसी असंतुलन की स्थिति बन सकती है। किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए वैज्ञानिक और पारंपरिक तरीकों का उपयोग कर जल संरक्षण व फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा।

सीमा पर बढ़ेगा तनाव और कूटनीति की होगी परीक्षा

ज्योतिषीय ग्रंथों में मंगल और शनि के संबंध को संघर्ष और शक्ति प्रदर्शन का कारक माना गया है। ज्योतिर्विद पं. अजय कृष्णशंकर व्यास के मुताबिक इस अवधि में विभिन्न राष्ट्रों के बीच आपसी तनाव और सीमा विवाद की घटनाएं बढ़ सकती हैं। वैश्विक मंचों पर आंतरिक सुरक्षा और सामरिक नीतियों पर गहन चर्चा होगी। युद्ध जैसी स्थितियों को टालने के लिए देशों के बीच कूटनीतिक प्रयासों में तेजी लानी पड़ेगी।

शिक्षा में होंगे बदलाव, युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर देना होगा ध्यान

यह गोचर बच्चों और युवाओं से जुड़े विषयों पर भी चुनौतियां दे रहा है। शिक्षा पद्धतियों और मानसिक विकास पर सरकारों का ध्यान केंद्रित होगा तथा शिक्षा क्षेत्र में कुछ कड़े सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। अभिभावकों को भी बच्चों की दिनचर्या, पोषण और डिजिटल तनाव से बचाव पर विशेष ध्यान देना होगा।

संकट से बचाव के लिए अचूक उपाय

गोचर के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए श्री मातंगी ज्योतिष केंद्र के ज्योतिर्विद पं. अजय कृष्णशंकर व्यास ने कुछ पारंपरिक उपाय बताए हैं। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन गरीबों या जरूरतमंदों को भोजन व आवश्यक वस्तुओं का दान कर शनि देव की आराधना करें।

नियमित रूप से प्रकृति और गौ-माता की सेवा करें। इस अवधि में अकारण विवाद से बचने के लिए अपनी वाणी और क्रोध पर पूरी तरह नियंत्रण रखना आवश्यक है।

एडीएम द्वारा विभिन्न मामलों में जनसुनवाई की गई

उज्जैन । एडीएम श्री अत्येन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा मंगलवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में विभिन्न मामलों में जनसुनवाई की गई।

घट्टिया तहसील के ग्राम निपानिया सुनार के रहवासियों ने आवेदन दिया कि गांव स्थित मंदिर में पुजारी के छोटे भाई द्वारा दस्तावेजों में हेराफेरी कर स्वयं की नियुक्ति करवा ली गई है। इस पर एडीएम ने एसडीएम घट्टिया को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बड़नगर तहसील के ग्राम माधवपुरा निवासी बंसीलाल ने आवेदन दिया कि उनकी स्वामित्व की कृषि भूमि पर गांव के एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इस पर तहसीलदार बड़नगर को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

घट्टिया तहसील के ग्राम उज्जैनिया निवासी जसपाल सिंह ने आवेदन दिया कि गांव में खेत की ओर जाने वाले शासकीय मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। इसके कारण स्थानीय लोगों को कृषि कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर एसडीएम घट्टिया को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार अपर कलेक्टर श्री शाश्वत शर्मा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा अन्य मामलों में भी जनसुनवाई की गई।

उज्जैन के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का नाम सावित्रीबाई फुले रखने की मांग

उज्जैन। शहर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखने की मांग उठी है। इस संबंध में अखिल भारतीय माली समाज विकास परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा को सौंपा है।

विधायक कालूखेड़ा वरिष्ठ नेताओं से भेंट के क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सांखला के निवास पर पहुंचे थे। इसी दौरान सांखला ने कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में विधायक को यह ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के लाखों अनुयायी निवास करते हैं।

सुरेंद्र सांखला ने कहा कि सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी हैं, जिन्होंने समानता और लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उज्जैन मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, ऐसे में उनसे अपेक्षा है कि वे इस मांग पर तत्काल निर्णय लें। नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का नामकरण सावित्रीबाई फुले के नाम पर होने से समाज में समानता के भाव को बल मिलेगा और यह माली समाज सहित समूचे पिछड़े वर्ग के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा।

महाराणा प्रताप जयंती पर शौर्य यात्रा निकलेगी

उज्जैन। श्री महाराणा प्रताप की 486 वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में 32 वीं शौर्य यात्रा 17 जून 2026 बुधवार की शाम 4 बजे महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत आरंम्भ होगी जो देवासगेट, दौलतगंज, कंण्ठाल, नईसड़क,कांग्रेस कार्यालय के सामने से क्षीरसागर होती हुई सामाजिक न्याय परिसर में सामाजिक समरसता सम्मेलन के रूप में परिवर्तित होगी,सम्मेलन के अतिथि श्रीमती लवली आनंदसिंह- सांसद,बिहार,श्रीमती रीनासिंह सुप्रीमकोर्ट एडवोकेट,श्री महेश सिंह ओमगांवकर-पूर्व एसपी,गोवा के आतिथ्य तथा राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनिलसिंह चंदेल की अध्यक्षता में होगा,जानकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर हरदयालसिंह एडवोकेट ने दी । शौर्ययात्रा का विभिन्न संस्थाओं से सौ मंचो से स्वागत किया जाएगा,शौर्य यात्रा में घोड़े, बग्गी,बैण्डदेशभक्ति के गीत बजते हुए।

,देशभक्त केसरिया पताकाएं पहरायेगे,समाजजन राजपूती गणवेश में शामिल होंगे,व्यवस्था की दृष्टि से कई कमेटियों का गठन किया गया है,जिसमें जिलाध्यक्ष-श्री जितेंन्द्रसिंह राजावत,युवावीग के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष-आनंन्द सिंह खींची,प्रदेश उपाध्यक्ष,नीरजसिंह चंदेल,जिलायुवावीग-अध्यक्ष शंकरसिंह पडिहार,युवावीग शहर-अध्यक्ष लोकेंन्द्रसिंह गौड़, कोषाध्यक्ष श्री मलखानसिंह दीक्षित सही कई पदाधिकारी को दायित्व सौपा गया है,सभी ने समाजजनों से आह्वान किया है कि राजपूती गणेश में शामिल हो।

111 बेटियों ने की ठाकुर जी के सम्मुख भावपूर्ण राग सेवा

उज्जैन। अधिक मास के समापन अवसर पर आचार्य महाप्रभु जी की बैठक में भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन संपन्न हुआ। यहाँ श्री वल्लभ वैष्णव मंडल, युवा मंडल एवं महिला मंडल के तत्वावधान में वेणुनाद निनाद नृत्य संस्थान की 111 बालिकाओं ने ठाकुर जी के सम्मुख भावपूर्ण राग सेवा प्रस्तुत की। संस्था की निर्देशिका पलक पटवर्धन के नेतृत्व और बैठक जी के ट्रस्टी विठ्ठल नागर के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रस्तुति को देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। एक ही यूनिफॉर्म में सजी बेटियों के अनुशासन और कलात्मक प्रदर्शन ने किसी राष्ट्रीय स्तर के बड़े कार्यक्रम की अनुभूति कराई।

संस्थान के सदस्य अंजलि चावड़ा, उन्नति बोलगे, अक्षरा जोशी, युग भार्गव और चंचल बोलगे के सहयोग से आयोजित इस सत्र में बालिकाओं ने मंगलाचरण से शुरुआत की। इसके बाद कृष्ण वंदना, अच्युतम केशवम, भये प्रकट कृपाला, मुकुंदा मुकुंदा, रामा अष्टक, मधुराष्टक, नाचे गिरधारी, राधे रानी दे डालो बंसी, आश्रय का पद और दृढ़ इन चरणन पर अत्यंत सुंदर प्रस्तुतियां दीं।

मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष जयेश श्रॉफ, सहसंयोजक आनंद पुरोहित, नूपुर नीमा, समन्वयक हेतल शाह, विशाल नीमा, युवा मंडल अध्यक्ष नितिन नीमा, कार्यकारी अध्यक्ष अमर दिशावल, बालकृष्ण नीमा, सुनील नीमा, संजय शाह, पवन त्रिपाठी, हेमंत जी, संजय सुगंधी, राजेंद्र नीमा, कविता श्रॉफ, श्रीमती वंदना जेथलिया एवं प्रमोद जेथलिया सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे।

कार्यक्रम के अंत में प्रसादी वितरण के साथ ही विगत एक माह से चल रहे अधिक मास के दर्शनों का क्रम संपन्न हुआ। अब अगला अधिक मास सिंहस्थ के पश्चात वर्ष 2029 में आएगा, हालांकि हवेली में नियमित दर्शनों का क्रम निरंतर जारी रहेगा।

वर्षा काल में बाढ़ और अतिवृष्टि से उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई

उज्जैन । एडीएम श्री अत्येन्द्र सिंह गुर्जर के द्वारा जिले में वर्षा काल में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण एवं जनमानस कि सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने के आदेश जारी कर दिए गए है। आदेश के अनुसार कंट्रोल रूम की स्थापना प्रशासनिक संकुल भवन के भू अभिलेख कार्यालय के अधीक्षक भू अभिलख के कक्ष में की गई है। कंट्रोल रूम का फोन नं. (0734-2513512) है।

उल्लेखनीय है कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष आगामी 15 अक्टूबर तक 247 प्रभावशील रहेगा। कंट्रोल रूम के नायब तहसीलदार श्री माधव प्रसाद मोंगरे होंगे। नियंत्रण कक्ष में शिफ्ट के अनुसार कर्मचारियों की ड्युटी लगाई गई है जो उपरोक्त फोन नंबर पर 24 घण्टे उपलब्ध रहेंगे और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सुचना मिलने पर उसे पंजी में दर्ज कर प्रभारी श्री माधव प्रसाद मोंगरे नायब तहसीलदार (9424697204) और संपुर्ण जिले में नोडल अधिकारी के रूप में समन्वयक श्री संतोष कुमार जाट डिस्ट्रीक्ट कमाण्डेन्ट होमगार्ड (9926769808) को अवगत करायेंगे।

महाकाल सिंधी कॉलोनी में 20 को होगा विशाल निरंकारी सत्संग आत्म मंथन

उज्जैन। शहर की महाकाल सिंधी कॉलोनी में आगामी शनिवार, 20 जून को आत्म मंथन के तहत एक विशाल निरंकारी सत्संग का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम हरियाणा के बल्लभगढ़ से पधार रहे महात्मा महेशजी के सानिध्य में संपन्न होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।

मीडिया सहायक विनोद गज्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह विशाल सत्संग सतगुरु माता सुदीक्षा जी और निरंकारी राजपिता के असीम आशीर्वाद और मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। इस दिव्य भक्ति उत्सव का मुख्य उद्देश्य आमजन को आत्म-मंथन, मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागृति की दिशा में प्रेरित करना है, ताकि समाज में प्रेम और सद्भावना का अधिक से अधिक संचार हो सके।

आयोजन के संबंध में मुखी त्रिलोक बेलानी ने बताया कि शनिवार को यह कार्यक्रम शाम 5-30 बजे से शुरू होकर 7-30 बजे तक चलेगा। आयोजन समिति ने शहर के सभी धर्मप्रेमियों और नागरिकों से इस सत्संग में सपरिवार उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। कार्यक्रम से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9827582395 पर संपर्क किया जा सकता है।

शा. कालिदास कन्या महाविद्यालय के बास्केटबॉल ग्राउंड पर हुआ शिविर का समापन कई खिलाड़ियों ने लिया खेल का लाभ

उज्जैन। म प्र शासन के खेल एवं युवक कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में जिला बास्केटबॉल व उज्जैन जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में तीस दिवसीय ग्रीष्मकालीन बास्केटबॉल खेल प्रशिक्षण शिविर स्थानीय शा. कालिदास कन्या महाविद्यालय के बास्केटबॉल ग्राउंड पर आयोजित किया गया। जिला बास्केटबॉल के वरिष्ठ विजय बाली व ओम सारवान ने बताया कि आयोजित शिविर में कई बालक-बालिकाओं ने खेल प्रशिक्षण शिविर का लाभ लिया और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

समापन जिला उज्जैन जिम्नास्टिक के वरिष्ठ ओ.पी. शर्मा की उपस्थिति में किया गया। खेल विभाग की बास्केटबॉल कोच सुनीता यादव ने बताया कि शिविर में सम्मिलित खिलाड़ियों के खेल के आधार पर ही आगामी स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों का टीम में चयन किया जाएगा। खिलाड़ियों के सर्वश्री ओपी शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट हर्षिता रॉय मोना, रिया करड़वाल, अंकिता गोंदिया, प्रमाण पत्र व मेडल प्रदान किए। साथ कई स्पर्धाओं का आयोजन भी इसी खेल सत्र में खिलाड़ियों खेलने का अवसर मिलेगा।

निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानको का पालन किया जाए- संभाग आयुक्त श्री सिंह

उज्जैन। संभाग आयुक्त सह सिंहस्थ मेला अधिकारी श्री आशीष सिंह ने मंगलवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माणाधीन एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन विकास प्राधिकरण श्री संदीप सोनी, सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संभाग आयुक्त श्री सिंह ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाए।

सिंहस्थ 2028 के तहत निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में नगर निगम, उज्जैन विकास प्राधिकरण तथा उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा सिंहस्थ-2028 को दृष्टिगत रखते हुए किए जा रहे विभिन्न विकास एवं अधोसंरचना निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। संभाग आयुक्त श्री सिंह ने सभी विभागों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित तरीके से कार्य संपादित करने के निर्देश दिए।

उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा के दौरान संभाग आयुक्त सिंह ने विक्रम कीर्ति मंदिर एवं वीर भारत संग्रहालय के निर्माण एवं विकास कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि यह परियोजनाएं उज्जैन की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान से जुड़ी हुई हैं, अतः इनके निर्माण में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए तथा विशेषज्ञों की सतत निगरानी में कार्य पूर्ण कराया जाए।

बैठक में मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के आसपास संचालित निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। संभाग आयुक्त श्री सिंह ने निर्देश दिए कि वर्तमान वर्षा ॠतु को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। साथ ही निर्माण स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं तथा श्रमिकों एवं आमजन की सुरक्षा के लिए सभी निर्माण सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए।उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन सिंहस्थ मेला कार्यालय की समीक्षा करते हुए संभाग आयुक्त ने निर्देश दिए कि यह भवन सिंहस्थ-2028 की व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण केंद्र होगा, इसलिए इसकी विशेष मॉनिटरिंग करते हुए उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने यूनिटी मॉल परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की तथा कार्यों की गति बढ़ाकर परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मेला अधिकारी श्री सिंह द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वर्षा ॠतु के दौरान निर्माण कार्यों में अतिरिक्त सावधानी बरती जाए तथा सभी परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए।

हवन-पूजन और विशाल भंडारे के साथ सिंधु सेना की सात दिवसीय भागवत कथा का समापन

मुकुंदाचार्य महाराज ने किया कृष्ण लीलाओं का वर्णन, महाआरती और छप्पन भोग में शामिल हुए शहर के कई गणमान्य नागरिक व सामाजिक संस्थाएं

उज्जैन। सिंधु सेना द्वारा आयोजित सात दिवसीय भागवत कथा का विधिविधान से हवन-पूजन और विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया। सात दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर धर्म लाभ लिया।

आयोजन में कथावाचक मुकुंदाचार्य महाराज द्वारा भगवान श्रीकृष्ण की विभिन्न लीलाओं का संगीतमय और विस्तार से वर्णन किया गया। समापन के अवसर पर किशोर मुलानी और विनोद मुलानी की ओर से महाआरती, छप्पन भोग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की।

कई सामाजिक संस्थाएं व संत रहे मौजूद-इस अवसर पर मुख्य रूप से साईं आतमदास महाराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूज्य पंचायत सतराम सिंधी कॉलोनी, सिंधु जागृत समाज, इंदिरा नगर सिंधी समाज, भाईबंध सिंधी पंचायत, राष्ट्रीय सिंधी मंच, भारतीय सिंधु सभा, झूलेलाल महिला मंडल, चामुंडा माता भगत समिति, नवग्रह शनि मंदिर समिति और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी व सदस्य भी शामिल हुए।

इनकी रही विशेष उपस्थिति-आयोजन में संतोष लालवानी, महेश परियानी, राजकुमार परसवानी, गिरधारी लालवानी, नरेंद्र सबनानी, दीपक वाधवानी, रितेश लालवानी, मनोज रोचवानी, राजेश कृष्णानी, ललित थावानी, सागर कृष्णानी, राम कुमरावत और अमित सोलंकी मौजूद रहे।

भोजन प्रसादी वितरण में विक्रम परजवानी और भरत धर्मदासानी की टीम का विशेष सहयोग रहा। मातृशक्ति के रूप में माया मुलानी, सुशीला परियानी, काम्या लालवानी, रोशनी मुलानी, वीना परसवानी, डिम्पल मुलानी, योगिता रोचवानी और कांता रोचवानी मुख्य रूप से उपस्थित थीं।

महाकाल मंदिर के अफसरों पर तानाशाही का आरोप, शिकायत के लिए विशेष समिति बनाने की मांग

उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में अधिकारियों की कथित तानाशाही और मनमानी को लेकर महाकाल सेना ने मोर्चा खोल दिया है। महाकाल सेना के राष्ट्रीय धर्म प्रकोष्ठ प्रमुख महेंद्र सिंह बैस ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उज्जैन कमिश्नर और कलेक्टर को पत्र भेजकर अधिकारियों की शिकायत के लिए एक विशेष समिति गठित करने की मांग की है।

पत्र में आरोप लगाया गया है कि महाकाल मंदिर का संचालन धार्मिक रीति-रिवाजों के बजाय एक सरकारी कार्यालय की तरह किया जा रहा है। अधिकारियों के दबाव और एफआईआर के डर से आम भक्त, ब्राह्मण समुदाय और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी भयभीत हैं। मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर भारी भेदभाव किया जा रहा है। यदि कोई पुजारी या पुरोहित अपने परिजनों अथवा भक्तों को नंदी हॉल या चांदी गेट से दर्शन कराना चाहता है, तो उसे नियमों का हवाला देकर अनुमति नहीं दी जाती। इसके विपरीत अधिकारी वर्ग अपने चहेतों और परिजनों को बिना किसी रोकटोक के सारी वीआईपी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। आरोप है कि चाटुकार प्रभारियों द्वारा अधिकारियों को गुमराह कर कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाता है, जिससे उन्हें हर समय नौकरी जाने का भय सताता रहता है।

महाकाल सेना ने मांग की है कि धार्मिक स्थलों पर नियुक्त अधिकारियों की निरंकुशता रोकने और उनके खिलाफ मिलने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाए। इस कमेटी में एक पूर्व न्यायाधीश, एक पत्रकार, क्षेत्रीय विधायक, मंदिर के पुजारी और महाकाल सेना का एक सदस्य शामिल हो।

इस व्यवस्था से पीड़ित भक्त, पुजारी और कर्मचारी न्याय के लिए गुहार लगा सकेंगे और सनातन मंदिर का संचालन सरकारी तानाशाही के बजाय बिना किसी भेदभाव के सुचारू रूप से हो सकेगा।

भावी पीढ़ियों के हिस्से का जल भी हमने धरती से निकाला, वाटर हार्वेस्टिंग ही एकमात्र विकल्पः सुधीन्द्र मोहन शर्मा

उज्जैन। जल प्रकृति का अनुपम उपहार है। पानी की हर बूंद जिंदगी देती है, लेकिन हमारे अत्यधिक लालच के कारण जल स्रोत संकट में हैं। हमने भूमि को कुछ दिया तो नहीं है, बल्कि इतना अधिक दोहन किया है कि भविष्य की पीढ़ियों के हिस्से का पानी भी धरती से निकाल लिया है। इससे भू-जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। अब प्रत्येक नागरिक को वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाकर भू-जल स्तर बढ़ाना होगा। यह बात जलशक्ति विभाग, भारत सरकार के पूर्व राष्ट्रीय नोडल अधिकारी (पेयजल सुरक्षा) सुधीन्द्र मोहन शर्मा ने कही।

वे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माधव महाविद्यालय में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। सुधीन्द्र मोहन शर्मा ने कहा कि सघन पौधारोपण करने के बजाय हमने केवल फोटो खिंचवा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। पेड़-पौधे और मिट्टी जल का संरक्षण करते हैं। मिट्टी को कवर करेंगे तो वह व्यर्थ बहने वाले पानी को सोख लेगी। माधव महाविद्यालय परिसर में प्रतिवर्ष औसतन ढाई करोड़ लीटर बारिश का पानी उपलब्ध होता है, जिसे सहेजने की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन और फिल्म नदिया के पार के माध्यम से भी जल संरक्षण का प्रभावी संदेश दिया।

स्वच्छ वायु के लिए लगाएं पीपल, बरगद और नीम

कार्यक्रम की सारस्वत अतिथि व सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान की पूर्व प्राध्यापक सुधा मल्ल ने कहा कि धरती से जुड़ाव हमारी संस्कृति का एक विशिष्ट पहलू है। प्रदूषण खत्म किए बिना पृथ्वी को नहीं बचाया जा सकता। यदि वायु प्रदूषण इंडेक्स 17 के ऊपर जाता है तो पौधों को नुकसान झेलना पड़ता है। स्वच्छ वायु के लिए हमें पीपल, बरगद और नीम जैसे पौधे लगाने चाहिए, साथ ही कुछ पौधे सुंदरता के लिए भी लगाए जाने चाहिए।

आगामी सिंहस्थ के लिए तैयार कर रहे परिसर

प्राचार्य कल्पना सिंह ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि यह परिसर भगवान कृष्ण और सुदामा की शिक्षा स्थली के पास स्थित है। आगामी सिंहस्थ के मद्देनजर हम शासकीय माधव महाविद्यालय को पर्यावरण और जल संरक्षण के दृष्टिकोण से तैयार कर रहे हैं। जल संवर्धन हेतु जागरूकता प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।

कार्यक्रम का संचालन वनस्पति विज्ञान विभाग के मनीष कुमार शर्मा ने किया और आभार प्रोफेसर अजीत केलवा ने माना। इस अवसर पर मौजूद प्राध्यापकों और शोधार्थियों ने पैनल चर्चा में भाग लेकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।

ज्ञान और ध्यान से मिटता है अज्ञान, सत्कर्मों से होती है धर्म की वृद्धि

उज्जैन। जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जिस तरह धूल से ढके दर्पण को साफ करने पर असली चेहरा दिखाई देता है, उसी तरह ज्ञान और ध्यान से अज्ञान नष्ट होने पर हृदय में विराजमान परमात्मा की अनुभूति होती है। यह बात अटल पीठाधीश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती ने मंगलवार शाम इंदिरानगर स्थित हरि सिंह यादव के निवास पर आयोजित एक दिवसीय प्रवचन में कही।

मांगलिक कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रवचन में स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती ने कहा कि जीवन का मुख्य लक्ष्य उपासना और धार्मिक कार्य है। सृष्टि की रचना का उद्देश्य धर्म की वृद्धि करना है। धर्म पेड़ों पर फल की तरह नहीं लगता, बल्कि यह मनुष्यों द्वारा किए गए सत्कर्मों से बढ़ता है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि सनातन परंपरा में विपरीत मान्यताओं के कारण धर्म में कमी आ रही है। जितने अधिक लोग श्रद्धा से सत्कर्म, तर्पण और पितरों की भक्ति करेंगे, धर्म उतना ही अधिक गुना बढ़ेगा। जहां धर्म होता है, वहीं बल होता है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए रवि राय ने बताया कि प्रवचन के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। आयोजन में समाजसेवी नारायण यादव, प्रेम सिंह यादव के साथ ही संत सत्कार समिति, युवा मंच सत्संग समिति और अंबे समिति के सदस्य व श्रद्धालु उपस्थित रहे।

नई शिक्षा नीति और एआई के दौर में शिक्षकों को बनना होगा टेक-सैवी

उज्जैन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और तकनीक के इस तेजी से बदलते दौर में शिक्षकों को निरंतर अपडेट रहना होगा। आज का विद्यार्थी तकनीक से भली-भांति परिचित है, इसलिए शिक्षक का टेक-सैवी होना भी आवश्यक है। पहले उत्कृष्ट शिक्षक की पहचान चाक एंड टॉक पद्धति से होती थी, लेकिन आज स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल संसाधन और एआई जैसे साधनों का प्रभाव बढ़ गया है। यह बात विद्या भारती शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के देवकीनंदन चौरसिया ने कही। वे लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति द्वारा आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग के पांचवें दिन 21वीं सदी के शिक्षक की भूमिका और चुनौतियां विषय पर बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता के विकास पर बल देती है। शिक्षक अब केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, मेंटर और फेसिलिटेटर है। विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए शिक्षक को विषय और समसामयिक ज्ञान बढ़ाना होगा। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा और मूल्य शिक्षा को शिक्षण का अभिन्न अंग बनाना होगा। विद्यार्थियों में बढ़ते तनाव को देखते हुए वर्तमान में शिक्षक का एक अच्छा काउंसलर होना भी जरूरी है।

शिक्षकों ने दी एआई और पर्यावरण संरक्षण पर प्रस्तुति

प्रशिक्षण वर्ग के प्रथम सत्र में शिक्षकों ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी प्रस्तुति दी। सत्र का संचालन अंजलि मोदी ने किया। इसमें दिव्या शुक्ला ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में शिक्षक की भूमिका पर बात की। प्रमोद जानी ने समाज सेवा, स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के महत्व को समझाया। सुधीर सोलंकी ने एआई सेक्टर के उभरते ट्रेंड्स और इसके नैतिक उपयोग पर विचार साझा किए। वहीं, डॉ. अंजलि शाह ने शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की भावना विकसित करने पर जोर दिया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ समापन

इससे पूर्व द्वितीय सत्र का शुभारंभ संगठन मंत्र एवं मां सरस्वती के समक्ष पुष्पांजलि के साथ हुआ। इसका संचालन आभा शर्मा ने किया। मंच पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी गिरीश भालेराव एवं लोकमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शैलेष त्रिपाठी उपस्थित रहे। तृतीय सत्र पूरी तरह मनोरंजन पर केंद्रित रहा, जिसमें शिक्षण समिति की विभिन्न इकाइयों के शिक्षकों ने भजन, गीत व नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी संयोजक डॉ. शैलेष त्रिपाठी ने दी।

ODOP Mart पर ऑनबोर्डिंग के लिए बटिक शिल्पकारों से आवेदन आमंत्रित

उज्जैन । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रेरणा से मध्य प्रदेश में ODOP Mart E-commerce Website का शुभारंभ होने जा रहा है। इस के लिए हस्तशिल्प विकास निगम भैरवगढ़ एवं जिला हाथकरघा कार्यालय के माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के अंतर्गत उज्जैन जिले के ODOP बटिक प्रिंट के क्षेत्र में उत्पादन कर रहे बटिक शिल्पकारों को ODOP Mart Platform पर ऑनबोर्डिंग के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के लिए हस्तशिल्प विकास निगम का पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है। ODOP योजना के अंतर्गत बटिक प्रिंट उज्जैन जिले का चयनित उत्पाद है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय शिल्पकारों को प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग तथा राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करना है। संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम भैरवगढ़ के लेखापाल सह प्रभारी ने उक्त जानकारी दी।

जिन शिल्पकारों के पास बटिक शिल्पकार संबंधी पंजीयन नहीं है, वे सत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम कार्यालय, भैरवगढ़ से निर्धारित प्रारूप में पंजीयन करवा कर ऑनबोर्डिंग के लिए पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। ऑनबोर्डिंग पात्रता एवं शिल्पी पंजीयन के लिए केन्द्र प्रभारी अमरसिंह सेनानी (9926600673) से संपर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज झारडा में 188.42 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सामाकोटा बैराज का लोकार्पण करेंगे

उज्जैन । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार 17 जून को उज्जैन जिले की झारडा तहसील स्थित सामाकोटा बैराज का लोकार्पण करेंगे। यह परियोजना छोटी कालीसिंध नदी पर निर्मित है और इससे क्षेत्र के किसानों को आधुनिक सूक्ष्म दाब सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि सामाकोटा बैराज परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 188.42 करोड़ रुपये है, इसकी जल संग्रहण क्षमता 17.57 मिलियन घन मीटर है, जिससे कुल 7236 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में पाइप पद्धति द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना से झारड़ा तहसील के 18 गांवों – नलखेड़ा, पनोडिया, नीमखेड़ा, घट्टिया जस्सा, मेलाखेड़ी, खोरियापदमा, खेरला, लसूड़ियानहाता, नागपुरा, छज्जुखेड़ी, देलाखेड़ी, डूंगरखेड़ी, खेड़ामद्दा, कसोन, डूंगरखेड़ा, महिदपुरिया, सोमचिड़ी एवं झारड़ा – के लगभग 11,093 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। परियोजना के अंतर्गत दो पंप हाउस का निर्माण किया गया है, जिनमें से पंप हाउस नंबर-1 से 5548 हेक्टेयर तथा पंप हाउस नंबर-2 से 1738 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी। बैराज की ऊंचाई 13 मीटर एवं लंबाई 1010 मीटर है, जिसमें 12 मीटर × 8.85 मीटर के कुल 11 गेट लगाए गए हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया जाएगा। इनमें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्मित महाविद्यालय के नवीन भवन की लागत 4.35 करोड़ रुपये, लोक शिक्षण विभाग द्वारा शासकीय कन्या हाई स्कूल सेमलिया, शासकीय कन्या हाई स्कूल महिदपुर रोड तथा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कुंडीखेड़ा के भवनों की प्रत्येक की लागत 1.48 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग द्वारा मोचीखेड़ा में नवीन 33/11 के.वी. उपकेंद्र की लागत 1.91 करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा झारड़ा क्षेत्र के आक्यालिम्बा, पीपल्याधुमा, गोगाखेड़ा, भादवा, डूंगरखेड़ा, बरखेड़ाबुजुर्ग, मकला, चितावद, धाबलासिया, लसूड़ियानहाटा, नागगुराड़िया, नलखेड़ा एवं शक्करखेड़ी में निर्मित 13 उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों की प्रत्येक की लागत 0.65 करोड़ रुपये शामिल है। कुल मिलाकर इन विकास कार्यों की अनुमानित लागत 207 करोड़ रुपये से अधिक है।

श्री सिंथेटिक्स कर्मचारी कांग्रेस की रैली आज, मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन

उज्जैन। कर्मचारियों के लंबित भुगतान एवं श्री सिंथेटिक्स की भूमि पर प्रस्तावित वन विभाग की परियोजना के विरोध में श्री सिंथेटिक्स कर्मचारी कांग्रेस द्वारा बुधवार 17 जून को रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

ऑर्गेनाइजिंग मजदूर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष एवं रैली संयोजक प्रकाश सोलंकी ने बताया कि रैली सुबह 12 बजे शहीद पार्क से प्रारंभ होगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए फ्रीगंज टावर पहुंचेगी।

इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि श्री सिंथेटिक्स की लगभग 115 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग द्वारा परियोजना प्रस्तावित की गई है। यह भूमि वर्तमान में माननीय कोलकाता हाईकोर्ट के लिक्विडेटर के अधीन है।

कर्मचारियों ने कहा कि जब तक श्री सिंथेटिक्स के कर्मचारियों का लंबित हिसाब-किताब एवं बकाया भुगतान नहीं किया जाता, तब तक प्रस्तावित परियोजना का विरोध जारी रहेगा। वर्ष 2006 में कंपनी बंद होने के बाद से कर्मचारी लगातार अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द लंबित भुगतान कराकर उनकी समस्या का निराकरण किया जाए।

संपादकीय

गैस मोनोपोली पर चोटः सरकारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वर्चस्व से दब रही प्रतिस्पर्धा

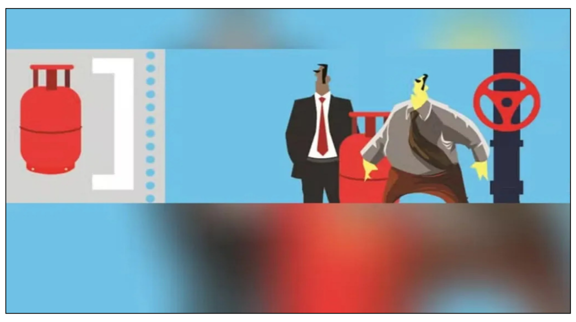

पश्चिम एशिया संकट के कारण देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की जो कमी बनी हुई है उसने आम परिवारों का प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल की ओर ध्यान आकर्षित किया है। भारत प्राकृतिक गैस और एलपीजी दोनों के मामले में आयात पर निर्भर है। घरेलू खपत के मामले में हम क्रमशः 50 से 60 फीसदी के लिए आयात पर निर्भर हैं। प्राकृतिक गैस के साथ अच्छी बात यह है कि इसके आयात के स्रोतों में विविधता लाई जा सकती है जबकि एलपीजी के आयात में विविधता लाना मुश्किल है।

घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल और गैस पर हमारी निर्भरता अब भी काफी अधिक है, और कुल ऊर्जा में इनका अनुपात पिछले दो दशकों में लगभग समान स्तर पर बना हुआ है।

जीवाश्म ईंधनों में प्राकृतिक गैस सबसे कम प्रदूषणकारी है। वर्ष 2070 तक विशुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण यह होगा कि प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए, जिसे कोयला गैस और बायोगैस (जहां भारत में अपार अप्रयुक्त क्षमता है) के साथ मिलाकर मध्यम अवधि में संक्रमण यानी बदलाव वाले ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।

दुर्भाग्यवश, विभिन्न दावों और सरकार के इस लक्ष्य के बावजूद कि 2030 तक प्राकृतिक गैस का हिस्सा कुल ऊर्जा मिश्रण में 15 फीसदी तक पहुंचेगा, वास्तविकता यह है कि यह अनुपात 2000 के लगभग 7-8 फीसदी से घटकर अब 5-6 फीसदी पर आ गया है।

हालांकि गैस क्षेत्र में कई मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है। यह लेख देश में गैस विपणन में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर केंद्रित है। ऊपर से नीचे की ओर एकीकृत सरकारी उपक्रम (पीएसयू), विशेष रूप से गेल, जो गैस संचरण और वितरण संचालन को जोड़ते हैं, दशकों से इन व्यवसायों पर हावी रहे हैं। गैस अधोसंरचना पूंजी-गहन व्यवसाय है जिसमें देर से प्रतिफल मिलता है। साथ ही, पूरे देश में सस्ती कीमतों पर ऊर्जा उपलब्ध कराना आवश्यक है, इसलिए कभी-कभी अव्यवहार्य लेकिन सामाजिक रूप से वांछनीय परियोजनाओं में निवेश की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार, गैस क्षेत्र के विकास के प्रारंभिक चरणों में पीएसयू का उच्चतम स्तर पर होना तर्किक लगता है। हालांकि, गैस क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता को देखते हुए और अधिक खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा लाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हो और परिचालन दक्षता में सुधार हो, सरकार ने दो दशक से अधिक पहले निजी क्षेत्र की भागीदारी को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की परिकल्पना की थी। यह उद्देश्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006 में परिलक्षित होता है। इस अधिनियम में, अन्य बातों के अलावा, गैस संचरण और वितरण गतिविधियों को अलग करने का प्रावधान है।

घरेलू प्राकृतिक गैस क्षेत्र की स्थिति समय के साथ काफी बदल गई है। उदाहरण के लिए, 2006 से 2024 तक गैस की खपत लगभग 85 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) से बढ़कर 188 एमएमएससीएमडी से अधिक हो गई, कुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क 7,112 किमी से बढ़कर 25,124 किमी से अधिक हो गया और सिटी गैस वितरण नेटवर्क की संख्या 33 से बढ़कर 307 भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंच गई।

अब वक्त आ गया है कि सरकारी उपक्रम गैस संचरण और वितरण में कुछ जगह निजी क्षेत्र के लिए बनाएं। नियामक को समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। पहले बात करते हैं गैस संचरण की।

गैस संचरणः ऊपर से नीचे की ओर एकीकृत संस्थाएं गैस संचरण और वितरण को अलग करने (अनबंडलिंग) का विरोध करती हैं। उनकी एकाधिकार शक्ति और अपारदर्शी मूल्य निर्धारण दस्तूर, संचरण व्यवसाय में किसी भी नए प्रवेश करने वाले की संभावना को लगभग समाप्त कर देती हैं।

पीएसयू द्वारा अनबंडलिंग के खिलाफ प्रस्तुत कारणों में से एक यह है कि इससे वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य पाइपलाइन परियोजनाओं में अपर्याप्त निवेश होगा, जो सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में आवश्यक हो सकती हैं। यह तर्क वास्तव में उनके व्यवसायों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाने के बारे में अधिक है। आखिरकार, वाणिज्यिक इकाइयों के दृष्टिकोण से, जिनमें से कुछ सूचीबद्ध हैं और सार्वजनिक शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह हैं, अव्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश को कब तक उचित ठहराया जा सकता है यह स्पष्ट रूप से एक अस्थिर नीति दृष्टिकोण है।

सही दृष्टिकोण यह होगा कि सामाजिक रूप से वांछनीय लेकिन अव्यवहार्य परियोजनाओं को पीएनजीआरबी द्वारा प्रशासित एक पारदर्शी वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना के माध्यम से वित्तीय समर्थन दिया जाए। यह योजना सभी पात्र संस्थाओं के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। वीजीएफ कोष परिवहन शुल्क पर उपकर लगाकर और असंतुलन शुल्क के माध्यम से एकत्रित धन का उपयोग करके स्थापित किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में, निम्नलिखित उपाय समयबद्ध तरीके से किए जाने चाहिएः

पीएनजीआरबी को ऊपर से नीचे एकीकृत संस्थाओं में विपणन और संचरण गतिविधियों को दो अलग-अलग कानूनी इकाइयों में विभाजित करने को सख्ती से लागू करना चाहिए।

कैसे ममता से दूर हुए शुभेंदु अधिकारी? TMC से BJP तक की पूरी राजनीतिक कहानी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार में शुभेंदु अधिकारी के एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की तैयारी के बीच ममता बनर्जी के कई समर्थकों को कुछ साल पहले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की कैबिनेट बैठक में हुई एक बातचीत को याद करना चाहिए। ममता ने अचानक हंगामा किया और उठकर बैठक से चली गईं। एक मंत्री ने झुंझलाकर कहा, 'ममता को क्या हो गया है!'

हालांकि मंत्री ने यह ऐसे ही बोल दिया था लेकिन वहां मौजूद प्रणव मुखर्जी ने इसका उत्तर देना उचित समझा। उन्होंने अपना चश्मा उतारा, उसे साफ किया, फिर से पहना और धीरे से कहाः 'अगर कोई यह सोचे कि वह रवींद्रनाथ ठाकुर से बेहतर कवि, बीथोवेन से बेहतर (संगीतकार) और लियोनार्दो दा विंची से बेहतर चित्रकार है, तो फिर उसके लिए सब कुछ एक समस्या है।'

यह ममता की ही अतिवादी सोच थी, और केवल उन्हीं की, जिसने शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से बाहर निकालकर भाजपा की गोद में धकेल दिया।

अधिकारी का प्रभाव क्षेत्र दक्षिण बंगाल है। उनके पिता ?शि?शिर अधिकारी कांग्रेसी और प्रभावशाली नेता थे, जो मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। वामपंथियों के वर्चस्व वाले कोंताई और तमलुक के इलाकों में,कांग्रेस का झंडा बुलंद था। वामपंथियों का साम्राज्य धीरे-धीरे ढहता गया, नंदीग्राम ने इसके पतन को और तेज कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने ही वामपंथियों द्वारा 'भूमि हड़पने' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

उनकी क्षमता को पहचानते हुए, ममता ने उन्हें टीएमसी युवा शाखा का अध्यक्ष और उस समय माओवादी समूहों के प्रभाव में रहे जंगलमहल के लिए पार्टी का पर्यवेक्षक बनाया। पांच साल से भी कम समय में, टीएमसी कांग्रेस और वामपंथी दलों, दोनों से यह राजनीतिक क्षेत्र छीनने में सफल रही। साथ ही क्षेत्र के उन युवाओं का विश्वास भी पुनः प्राप्त करने में कामयाब रही जो वामपंथी उग्रवाद की ओर अग्रसर हो रहे थे।

उनका उदय प्रभावशाली रहा। 2009 में, शुभेंदु तमलुक से लोक सभा के लिए चुने गए, उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता लक्ष्मण सेठ को 1,72,000 वोटों से हराया। वर्ष 2014 में उन्होंने माकपा के इब्राहिम अली को हराकर तमलुक संसदीय सीट बरकरार रखी।

टीएमसी ने 2016 में उन्हें नंदीग्राम विधान सभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला वाम मोर्चा और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार अब्दुल कादिर शेख से था। शुभेंदु ने 67 फीसदी से अधिक वोट प्राप्त करके जीत हासिल की। उनकी शानदार जीत के बाद ममता ने उन्हें परिवहन मंत्री बनाया। वर्ष 2018 में उन्हें पर्यावरण मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया। लेकिन ममता उनके बढ़ते प्रभाव से चिंतित होने लगीं।

इसके अलावा, उनकी अपनी उत्तराधिकार योजना थी जिसमें शुभेंदु का कोई स्थान नहीं था। लेकिन वह उनके सिद्ध राजनीतिक कार्यों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकीं, इसलिए एक समानांतर संगठन, टीएमसी युवा बनाया गया और उनके भतीजे अभिषेक को इसका प्रमुख चुना गया। बाद में उन्होंने टीएमसी युवा को भंग कर दिया और टीएमसी की युवा शाखा को पुनर्जीवित कियाः एक बार फिर अभिषेक के नेतृत्व में। शुभेंदु का उपयोग पार्टी को मजबूत करने के लिए किया गया, लेकिन उन्हें ममता के करीबी लोगों में कभी शामिल नहीं किया गया।

वह भी दरबारी कहलाना पसंद नहीं करते थे। विधायक के रूप में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह कभी भी कोलकाता में रात न बिताएं। वह प्रतिदिन अपने निर्वाचन क्षेत्र से राज्य की राजधानी तक 200 किलोमीटर की दूरी तय करते थे, कभी-कभी रात के 1 बजे घर पहुंचते थे और फिर सुबह जल्दी काम पर जाने के लिए निकल जाते थे।

मुख्यमंत्री और उनके सबसे महत्त्वपूर्ण मंत्री के बीच विश्वास की कमी स्पष्ट हो गई। उन्होंने एक बार कहा था, 'मैं परिवहन मंत्री था, लेकिन मंत्रालय ममता चला रही थीं।' अपमानों का सिलसिला बढ़ता ही गया। इन सबके मूल में 'शुभेंदु और अभिषेक के बीच की प्रतिद्वंद्विता थी। वर्ष 2020 में दुर्गा पूजा के दौरान तो ऐसा लगा मानो मतभेद सुलझ ही नहीं सकते। शुभेंदु के निर्वाचन क्षेत्र में उनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में हर जगह पोस्टर लगे हुए थे जिन पर लिखा थाः 'दादार अनुगामी (दादा का अनुयायी)।'

आधिकारिक तौर पर शुभेंदु ने इस बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया। लेकिन इन कार्यक्रमों में टीएमसी का कोई बैनर या ममता की तस्वीर नहीं थी। इसी बीच, टीएमसी नेता नंदीग्राम गए और वहां एक बैठक की, जिसमें उन्हें 'मीर जाफर' कहकर संबोधित किया गया। उसी वर्ष के अंत में 2021 के विधान सभा चुनावों से पहले शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हो गए।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद, ममता की अपनी पार्टी पर ऐसी पकड़ थी कि नेताओं को पता था कि उन्हें उनकी हर जिद पूरी करनी होगी अन्यथा दरकिनार कर दिया जाएगा। इसके चलते कुछ ऐसे अप्रत्याशित परिणाम सामने आए कि कई नेताओं को, जो यह मानकर चल रहे थे कि उनका राजनीतिक भविष्य बहुत उज्ज्वल है, ममता द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद यह पता चला कि उन्हें आखिर क्यों बाहर का रास्ता दिखाया गया था। उदाहरण के लिए, उन्हें दरकिनार किए जाने के कारणों में ममता के गाते समय रवींद्र संगीत को पूरी एकाग्रता के साथ न सुनना या ममता की बताई दवाएं न लेना (वह खुद को डॉक्टर समझती हैं) शामिल हैं।

अब जब ममता मुश्किल हालात में खड़ी हैं, तो उन्हें खुद का, उन सभी लोगों का जिन्हें उन्होंने खुद से दूर कर दिया है, गहराई से आकलन करने की जरूरत है और खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर क्यों उनकी दुनिया उनके पैरों के पास ही खंडहर बनकर बिखर गई है।

क्या Vodafone Idea वापसी कर पाएगी? कर्ज, 5G और भरोसे की बड़ी चुनौती

वोडाफोन आइडिया (वी) ने उद्योग जगत और ऋणदाताओं को संकेत दिया है कि उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला के कंपनी में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वापस आने के साथ वह अपनी रणनीति को और मजबूत कर रही है। हालांकि बिड़ला ने दूरसंचार क्षेत्र के दो कंपनियों के एकाधिकार में तब्दील होने की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया है, लेकिन 49 फीसदी सरकारी हिस्सेदारी वाली यह संघर्षरत कंपनी अभी तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों का भरोसा जीतने में सफल नहीं हुई है। इसके प्रवर्तकों ब्रिटेन स्थित वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिड़ला समूह ने, जिनकी संयुक्त हिस्सेदारी 25.64 फीसदी है, सरकारी हस्तक्षेप का आग्रह किया था और संकेत दिया था कि नुकसान वाली जगह पर बेकार का निवेश नहीं किया जाना चाहिए। अब, सरकार द्वारा वोडाफोन के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित बकाया राशि की व्यापक समीक्षा और कंपनी के कुछ बकाया को अपनी इक्विटी में परिवर्तित करने सहित कई लाभ और रियायतें देने के बाद, वोडाफोन के प्रवर्तकों को यह दिखाना होगा कि वे कंपनी में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हाल ही में मीडिया से बातचीत में बिड़ला ने कहा कि वोडाफोन के परिचालन संबंधी मापदंडों में ठोस सुधार दिखना शुरू हो गया है और इस गति को 5 अरब डॉलर की पूंजीगत व्यय योजना से सहारा मिलेगा। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि कंपनी के पुनरुद्धार से 'तीन प्रमुख कंपनियों वाले स्वस्थ निजी बाजार' को बनाए रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, खबरों के मुताबिक, बैंकों ने वोडाफोन के लगभग 35,000 करोड़ रुपये के ऋण अनुरोध पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है और उनका कहना है कि दूरसंचार कंपनी को उनके साथ अपना संपर्क बढ़ाना होगा।

मुख्य मुद्दा यह है कि ऋणदाता डिफॉल्ट की स्थिति में अतिरिक्त पूंजी लगाने के लिए प्रवर्तकों से गारंटी और प्रतिबद्धता चाहते हैं। वोडाफोन द्वारा इस तरह का कोई आश्वासन देने का अभी तक कोई सबूत नहीं है। वोडाफोन के एजीआर बकाये में 27 फीसदी की कमी के बाद भी, जो लगभग 87,695 करोड़ रुपये से घटकर लगभग 64,046 करोड़ रुपये हो गया है, दूरसंचार ऑपरेटर को अगले तीन वर्षों में स्पेक्ट्रम बकाये के लिए काफी अ?धिक रा?शि का भुगतान करना होगा। हालांकि, इसका एजीआर बकाया वित्त वर्ष 2036 से छह वर्षों में छह किस्तों में दिया जाना है, जो एक बड़ी राहत है।

बैंकों के लिए वोडाफोन का लगभग 2.1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज एक बड़ी चुनौती है। इसलिए, वे और फंड देने से पहले प्रवर्तकों की गारंटी पर जोर दे रहे हैं। कुछ साल पहले तक बाजार में अग्रणी मानी जाने वाली यह कंपनी ग्राहकों की संख्या और प्रति उपयोगकर्ता औसत मासिक राजस्व (एआरपीयू) में वृद्धि के मामले में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है।

ऐसे समय में जब तकनीकी प्रगति सभी क्षेत्रों में विकास की गति को बढ़ा रही है, वोडाफोन ने अपने ग्राहकों को 5जी सेवा प्रदान करने में देर से शुरुआत की। अब जब दूरसंचार क्षेत्र 6जी और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जैसे क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है, वोडाफोन को एक विश्वसनीय दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो उपयोगकर्ताओं का विश्वास जगा सके और ऋणदाताओं को आश्वस्त कर सके।

सरकार ने वोडाफोन को कई तरह से सहारा दिया है ताकि यह क्षेत्र दो कंपनियों के एकाधिकार में न फंस जाए। अब सरकार को करों और शुल्कों की समीक्षा करके व्यवस्थागत समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ऑपरेटरों पर बोझ कम हो सके, जिन्हें लगातार नई तकनीक में निवेश करना पड़ता है। वोडाफोन की बात करें तो, भले ही अभी स्थिति सकारात्मक दिख रही हो, दूरसंचार कंपनी को अपने वादों को ठोस रूप देने के लिए कदम उठाने होंगे। पिछले कुछ वर्षों में इसने धन जुटाने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन अब इसे इस दिशा में और अधिक सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। सेवा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ टैरिफ को तर्कसंगत बनाना भी एक ऐसा कदम है जिस पर कंपनी और उद्योग को विचार करना चाहिए। इससे भारत में दूरसंचार का भविष्य अधिक सुरक्षित होगा।

बंगाल का 'रक्त-चरित्र'

बेशक पश्चिम बंगाल में 'परिवर्तन' का जनादेश दिया गया है और आज पहली भाजपा सरकार शपथ ग्रहण कर रही है, लेकिन बंगाल का 'रक्त-चरित्र' नहीं बदला है। जनादेश के बाद बंगाल का 'बदलापुर' सामने है। चुनाव के बाद हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफ़ोड़, कब्जेबाजी और बुलडोजर सरेआम दिख रहे हैं। पांच राजनीतिक हत्याएं की जा चुकी हैं। उनमें घोर निर्मम हत्या सुवेन्दु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की है। सुवेन्दु भाजपा सरकार के भावी मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं। गौरतलब है कि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी घरेलू सीट 'भवानीपुर' में पराजित किया है। चंद्रनाथ राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। वायुसेना से सेवानिवृत्त थे। वह सुवेन्दु के साथ तब से कार्यरत थे, जब सुवेन्दु ममता सरकार में मंत्री थे और मुख्यमंत्री के भरोसेमंद नेता थे। हमलावरों ने चंद्रनाथ को उनके घर से 100-150 मीटर दूर ही गोलियों से भून दिया। हमलावर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन एसआईटी की जांच जारी है। ममता बनर्जी ने अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है, जिसे तृणमूल नेता दोहरा रहे हैं। सुवेन्दु अधिकारी का मानना है कि हमलावरों के निशाने पर वह थे, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को हराया है, लेकिन उनके सहायक की हत्या कर दी गई। यह पूर्व नियोजित, साजिशाना, नृशंस हत्या है। हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल यह हत्या ही बंगाल के 'रक्तचरित्र' को बयां करती है। हालांकि चुनाव और जनादेश के बाद भाजपा कार्यकर्ता मधु मंडल और तृणमूल के कार्यकर्ता अबीर शेख की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ता को भी मारा गया है, जबकि बंगाल में कांग्रेस के अवशेष ही बचे हैं। बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, टॉलीगंज, हुगली, बांकुरा, आसनसोल, बीरभूम, जलपाईगुड़ी से 24 परगना तक हिंसा का जो 'नंगा नाच' सामने आया है, उनके 'रक्तबीज' कौन हैं? कमोबेश बंगाल से 'भद्रलोक' का सम्मानजनक विशेषण छीन लेना चाहिए, क्योंकि अब वह मुखौटा भर है, क्योंकि राजनीतिक हिंसा और हत्याओं में बंगाल देश में शीर्ष स्थान पर है। यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। इस बार भी 400 से अधिक जगहों पर हिंसा, तोडफ़ोड़, आगजनी की घटनाएं हुई हैं। 200 से अधिक अप्राथमिकी दर्ज की गई हैं, 433 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं और करीब 1100 लोग हिरासत में लिए गए हैं। राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों के 2.40 लाख जवान तैनात किए गए थे। सीएपीएफ की 500 कंपनियां और तैनात की जा रही हैं, लेकिन बंगाल का 'रक्तचरित्र' यथावत है, कोई अंकुश नहीं, कोई बदलाव नहीं।

बेशक प्रधानमंत्री मोदी 'बदला नहीं, बदलाव' की अपील करते रहें। इस बार चुनाव के दौरान अपेक्षाकृत बहुत कम हिंसा हुई। हत्या कोई नहीं हुई थी, लेकिन चुनाव और जनादेश के बाद बंगाल का 'रक्तरंजित' चरित्र सामने आ गया। दरअसल बंगाल में जो 'रक्तबीज' कांग्रेस ने बोया था, उससे पैदा हिंसा की फसलों को वाममोर्चे की सत्ता के दौरान 'संस्थानगत' आकार दिया गया। तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, तो वामदलों के गुंडे, अपराधियों ने निष्ठाएं बदल लीं और तृणमूल के साथ जुड़ गए। नतीजतन 15 साल की सत्ता के दौरान हिंसा, हत्या, दादागीरी, गुंडई और इलाकाई बदमाशी का एक 'इकोसिस्टम' तैयार हो गया। तृणमूल के गुंडे, हमलावर आज भी उसी सिस्टम की धमकियां दे रहे हैं, लिहाजा भाजपा सरकार के सामने सबसे विराट चुनौती यही है कि उस सिस्टम को प्राथमिकता के साथ कुचला जाए। अब जनादेश के बाद उन दफ्तरों को छुड़ाने के लिए उत्पात मचाए जा रहे हैं, जिन पर किसी अन्य दल ने कब्जा कर लिया था। ऐसे हमले तृणमूल के दफ्तरों पर अधिक हो रहे हैं। तृणमूल दफ्तरों पर बुलडोजर चलाने की भी खबरें हैं। बहरहाल बंगाल के 'रक्तचरित्र' के लिए ममता बनर्जी और उनके सांसद-भतीजे अभिषेक बनर्जी को माफ नहीं किया जाना चाहिए। अभिषेक ने 'जल्लाद', 'दिल्ली में बाप' और 'अमित शाह बंगाल में घुस कर दिखाए' सरीखे शब्दों और वाक्यों का जो इस्तेमाल किया था, उस पर हिंसा और हत्याओं की सुई केंद्रित क्यों न की जाए?

क्या बुद्धिजीवी आएंगे चुनाव में

नगर निगम चुनावों में सत्ता के पक्ष और विपक्ष के कद का मुकाबला आहूत है। प्रथम कदम उठाती भाजपा ने परिदृश्य को विस्तार देते हुए चुनाव को इतना महत्त्वपूर्ण बना दिया कि अब कांग्रेस ने नगरों के चूल्हे चौंके पर तमाम हमाम चढ़ा दिए हैं। ऐसे में छावनी बन गए नगर निगम हिमाचल की सियासत को नए प्रयोगों की जमीन बना कर ही छोड़ेंगे। यह इसलिए भी कि कुछ निर्दलीय वोटों को बटोरने की क्षमता में, दोनों प्रमुख दलों की कोशिशों को बट्टा लगा सकते हैं या अंतर्विरोध की तालिका में सपने बिगाड़ सकते हैं। सियासत सुर पकडऩे की कोशिश में आमने सामने है, तो चुनाव के कोरिडोर में सिर धड़ की बाजी सामने आ रही है। जाहिर है चुनाव पूरी तरह राजनीति में रंगे हैं, तो प्रचार की सामग्री में धब्बे और कीचड़ ही उछलेगा। खैर पालमपुर, मंडी, धर्मशाला व सोलन की जनता के सामने अपनी राजनीतिक-सामाजिक जागरूकता दर्ज कराने का अवसर भी तो है। राज्य की चिंताएं शहरों के वजूद से निकलेंगी तो राज्यस्तरीय खाकों में योजनाओं की जरूरत बढ़ेगी। शहर वे भी हैं जहां नगरपरिषदें या पंचायतें हैं, लेकिन निगमों के प्रारूप में हिमाचल क्या सोचता, यह इम्तिहान जरूरी है। सामाजिक तौर पर बुद्धिजीवी वर्ग की राजनीतिक या लोकतांत्रिक उदासीनता अगर यूं ही जारी रही, तो पार्षदों के रूप में हमें केवल कुछ सियासी खंभे ही मिलेंगे। देखना यह भी होगा कि चुनावी वादों का मानचित्र क्या बनता है और कितनी इच्छाशक्ति से पार्टियां अपने संकल्प पत्र तैयार करती हैं।

विडंबना यह है कि शहरी सोच ने आर्थिक घरौंदे बना कर सारी व्यवस्था को उलट पलट दिया है। सोलन की अपनी शहरी दृष्टि पर चढ़ा नकाब यह देख ही नहीं पाता कि कल की हरी भरी पहाडिय़ां आज सीमेंट के बुर्ज बन गई हैं। पालमपुर ने छीन लिए चाय के बागीचे और अब साथ लगती पहाडिय़ों पर पर्यटन के नाम पर इन्हें छीलने का काम जारी है। धर्मशाला अपने अस्तित्व की बुलंद तस्वीर बनाते मकलोडगंज को 'मैलागंज' बना चुका है तो आर्थिक तरक्की का सूरमा बन कर लैंड माफिया राज कर रहा है। मंडी का संघर्ष अपनी ही सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन जिक्र यह कि भाजपा इसे अपनी सियासत का चश्मदीद गवाह बनाना चाहती है। क्या हम मंडी को सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा देने के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। क्या सोलन को सुरक्षित अपार्टमेंट सिटी का खिताब हासिल करने का शोर ये चुनाव उठाएंगे। क्या पालमपुर अपने भीतर के 'पलम' को जिंदा रखते हुए चाय और कूहलों में बहते पानी को जिंदा रखने का चुनावी एहसास कराएगा या भीड़ के आलम में हम एक गिनती का बड़ा शहर बन जाएंगे।

धर्मशाला को कई तखल्लुस मिले, लेकिन मिनी ल्हासा, शीतकालीन राजधानी, खेल नगरी या पर्यटन राजधानी के बिल्लों के नीचे, इसे चुनाव के सीने में कोई सरोकार मिलेंगे। शहरी चुनाव की भुजाओं बिलासपुर में नए सेक्टरों की ईजाद, नाहन अपने तालाबों से रिसते फरमान या चंबा के चौगान अपनी खो रही मुस्कान को फिर से हासिल कर पाएंगे।

दुनिया बड़े फार्म देखती रही, ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत ने दिखा दी छोटे किसान की ताकत

इंदौर। दुनिया की कृषि नीति लंबे समय तक उत्पादन, निर्यात और बड़े कृषि फार्मों के इर्द-गिर्द घूमती रही। अधिक पैदावार, अधिक मशीनीकरण और बड़े पैमाने पर खेती को कृषि विकास का मानक माना गया। जबकि इंदौर में हुई ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की घोषणा एक अलग कहानी कहती है। यह दस्तावेज बताता है कि भविष्य की खेती का सबसे महत्वपूर्ण पात्र बड़ा कृषि उद्यम नहीं, बल्कि छोटा किसान होगा।

इंदौर घोषणा से एक बात स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है कि इसमें छोटे और पारिवारिक किसानों का उल्लेख बार-बार किया गया है। खाद्य सुरक्षा से लेकर जलवायु परिवर्तन, कृषि व्यापार, तकनीक, बीज, वित्त और ग्रामीण विकास तक लगभग हर विषय को छोटे किसानों के नजरिए से देखने का प्रयास किया गया है।

खाद्य सुरक्षा की असली नींव हैं छोटे किसान- यह बदलाव संयोग नहीं है। ब्रिक्स देशों में दुनिया की बड़ी आबादी रहती है और करोड़ों किसान आज भी छोटे जोत क्षेत्र पर खेती करते हैं। भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य सदस्य देशों के अनुभव बताते हैं कि खाद्य सुरक्षा की असली नींव छोटे किसानों के हाथों में ही है। ऐसे में यदि जलवायु परिवर्तन, बाजार अस्थिरता या उत्पादन संकट का असर सबसे पहले किसी पर पड़ता है तो वह यही वर्ग है।

भारत के लिए यह दृष्टिकोण और भी महत्वपूर्ण है। देश के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत वर्ग में आते हैं। उनकी औसत जोत छोटी है, संसाधन सीमित हैं और जोखिम उठाने की क्षमता कम है। बावजूद देश की खाद्य सुरक्षा का बड़ा भार उन्हीं के कंधों पर है। यही कारण है कि इंदौर घोषणा में तकनीक, वित्त, बीमा, बाजार और नवाचार को बड़े कृषि कारोबार की बजाय छोटे किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिखाई देता है।

भारतीय कृषि सोच की दिखी स्पष्ट छाप- पिछले कुछ वर्षों में भारत ने प्राकृतिक खेती, किसान उत्पादक संगठनों, डिजिटल कृषि, महिला किसानों की भागीदारी और स्थानीय फसलों को बढ़ावा देने जैसी पहलों पर जोर दिया है। इन विषयों की स्पष्ट छाप इंदौर घोषणा में भी दिखाई देती है।

दस्तावेज का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें किसानों को केवल उत्पादक नहीं, बल्कि पारंपरिक ज्ञान, जैव विविधता और बीज विरासत के संरक्षक के रूप में भी स्वीकार किया गया है। यानी कृषि को केवल आर्थिक गतिविधि नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के रूप में देखने की कोशिश की गई है। समिति संसाधनों में भी दुनिया को दे रहे अन्न- इंदौर घोषणा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भविष्य की कृषि नीति का मूल्यांकन केवल उत्पादन के आधार पर नहीं होगा। यह भी देखा जाएगा कि खेती कितनी टिकाऊ है, किसानों की आय कितनी सुरक्षित है और छोटे किसान नई तकनीक तथा बाजार तक कितनी पहुंच बना पा रहे हैं।

इसी मायने में इंदौर घोषणा केवल कृषि सहयोग का दस्तावेज नहीं, बल्कि वैश्विक कृषि सोच में बदलाव का संकेत है। यह बताती है कि भविष्य की खाद्य सुरक्षा केवल बड़े खेतों और भारी निवेश से नहीं, बल्कि उन करोड़ों छोटे किसानों से तय होगी जो सीमित संसाधनों के बावजूद दुनिया की थाली भर रहे हैं। भारत ने इसी सोच को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की कोशिश की है।

इंदौर को मिलेगी बड़ी सौगात... 6 रूटों पर दौड़ेंगी 26 हाईटेक इलेक्ट्रिक बसें

इंदौर। इंदौर से जल्द ही सार्वजनिक परिवहन के नए और आधुनिक दौर की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत छह रूटों पर 26 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए एआईसीटीसीएल द्वारा टेंडर जारी किए गए हैं। अनुबंध के तहत इन बसों को जुलाई माह से शुरू होने वाली नई बस सेवा में शामिल किया जाएगा। यह पहल यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर के अलावा शहर में हरित और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी मजबूती प्रदान करेगी।

टेंडर प्रक्रिया और अनुबंध की शर्तें- राज्य सरकार जुलाई में इंदौर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसों का संचालन शुरू कर रही है। पहले चरण में अनुबंध के आधार पर 12 मीटर इलेक्ट्रिक इंजन वाली 26 बसें चलाने की योजना है। इसके लिए 22 जून तक टेंडर बुलाए गए हैं। तीन वर्ष बस संचालन का अनुभव रखने वाले ऑपरेटर इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ऑपरेटर के लिए 10 करोड़ का टर्नओवर होना जरूरी है। एक या तीन ऑपरेटर एक साथ भी टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। 23 जून को तकनीकी बिड खोली जाएगी। इसमें सफल रहने पर ऑपरेटर और एआईसीटीसीएल के बीच दस साल बस संचालन का अनुबंध होगा। बाद में अनुबंध को दो वर्ष आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा। चयनित ऑपरेटरों को नई इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध करानी होगी। ऑपरेटरों को इलेक्ट्रिक बस संचालन के लिए बस डिपो के अलावा रूट पर और अंतिम पड़ाव पर चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था करनी होगी।

सरकार की तरफ से 40 प्रतिशत अनुदान

अनुबंध करने वाले ऑपरेटर को नई इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर सरकार की तरफ से बस की कीमत या 1.50 करोड़, जो भी कम हो, का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान चार चरणों में मिलेगा। रूट प्लानिंग, सर्विस स्टैंडर्ड्स और ऑपरेशनल मॉनिटरिंग एआईसीटीसीएल करेगा। वहीं बस ऑपरेटर को सुरक्षित और कस्टमर-ओरिएंटेड सर्विस देनी होगी।

बसों में एआईएस-140 मानकों के अनुरूप जीपीएस आधारित व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) लगाई जाएगी। यह सिस्टम सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़ा रहेगा, जिससे बसों की लोकेशन और संचालन की निगरानी रियल टाइम में होगी। हर बस में पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे। बस में दो सीसीटीवी कैमरों से पूरे यात्री क्षेत्र और ड्राइवर के केबिन की रिकॉर्डिंग होगी।

इंदौर एयरपोर्ट पर खराब मौसम की मार... पुणे की उड़ान की लैंडिंग फेल, वड़ोदरा किया गया डायवर्ट

इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट पर रविवार सुबह तेज वर्षा के कारण पुणे से आई उड़ान की लैंडिंग नहीं हो सकी। पायलट को रनवे स्पष्ट नहीं दिखाई देने के कारण लैंडिंग में असफल रहने पर विमान को डायवर्ट कर वड़ोदरा भेजा गया। यह विमान करीब दो घंटे बाद सुबह 8.30 बजे इंदौर लौट आया। विमान डायवर्ट होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी और घंटों का अतिरिक्त सफर करना पड़ा।

रनवे स्पष्ट न दिखने पर पायलट ने एटीसी को दी सूचना, यात्रियों में बढ़ी बेचैनी

इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 284 पुणे से उड़ान भरकर सुबह 6.40 बजे इंदौर पहुंची थी, लेकिन यहां पर खराब मौसम के कारण पायलट को रनवे स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। पायलट ने एटीसी को इसकी सूचना दी और विमान को वड़ोदरा एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट किया गया। विमान की लैंडिंग विफल रहने से इसमें सवार यात्रियों की बेचैनी बढ़ गई। वापस इंदौर आने पर ही यात्रियों की जान में जान आई।

वहीं, छह विमान भी विभिन्न कारणों से देरी से संचालित हुए। एयरपोर्ट के पीआरओ रामस्वरूप यादव ने कहा कि खराब मौसम के कारण एक उड़ान की लैंडिंग में परेशानी आई थी, इसलिए सुरक्षा के तहत अन्य एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया।

इंदौर की बदलेगी तस्वीर... भूजल स्तर सुधारने के लिए बनेंगे तालाब और चेकडैम, जंगलों में रोपे जाएंगे 2.81 लाख पौधे

इंदौर। पेड़ों की लगातार कटाई और कम होती हरियाली का असर अब पर्यावरण के साथ-साथ भूजल की स्थिति पर नजर आने लगा है। शहरों में बढ़ते जल संकट को देखते हुए इंदौर वनमंडल ने अब जंगलों में हरियाली बढ़ाने और जल संरक्षण पर भी काम शुरू कर दिया है। वन विभाग ने जंगलों में पौधारोपण के साथ ऐसे इंतजाम किए हैं, जिससे बारिश का पानी रुके और भू-जल स्तर बढ़ सके, ताकि गर्मियों के दिनों में वन्यप्राणियों को पानी की कमी न हो सके।

जल संरचनाओं का निर्माण और पौधारोपण अभियान- इंदौर वनमंडल द्वारा वार्षिक पौधारोपण के अंतर्गत जंगलों में छोटे-छोटे तालाब, चेकडैम और कंटूर सहित अन्य जल संरचनाएं बनाई जाएंगी। जून-जुलाई में होने वाले पौधारोपण अभियान के दौरान इन कामों को भी गति दी जाएगी। इंदौर-चोरल, महू और मानपुर क्षेत्र के जंगलों में करीब 2 लाख 81 हजार पौधे लगाए जाएंगे। यह पौधारोपण 20 अलग-अलग वन क्षेत्रों में किया जाएगा। इन क्षेत्रों में पौधों की सुरक्षा के साथ पानी की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वन विभाग पहले से बने तालाबों का गहरीकरण भी करेगा, ताकि उनमें ज्यादा मात्रा में बारिश का पानी जमा हो सके। इससे गर्मियों में जंगलों में पानी की कमी कम होगी और वन्यजीवों को भी फायदा मिलेगा।

मुरझाए पौधों को बदलेंगे- पिछले साल लगाए गए पौधों में से करीब 20 से 22 प्रतिशत पौधे खराब हो गए हैं। इंदौर, महू, मानपुर और चोरल रेंज में मुरझाए पौधों को बदला जाएगा। वन विभाग ने ऐसे करीब 84 हजार पौधों की पहचान की है। अब इनकी जगह नए पौधे लगाए जाएंगे। यह काम जुलाई और अगस्त के बीच किया जाएगा।

दतुनि पहाड़ी पर बनेगा नगर वन- इंदौर वनमंडल नगर वनों को विकसित करने में लगा है। देवगुराडिया पहाड़ी पर नगर वन के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, जिसमें वॉकिंग ट्रैक, प्रकृति पथ, तालाब, बटरफ्लाई गार्डन, औषधीय पौधों के क्षेत्र और बैठने की सुविधा की गई है। इस बार पहाड़ी के दूसरे हिस्से में आठ हजार पौधे रोपे जाएंगे।

यह नगर वन के दूसरे चरण में काम होंगे, जबकि दूसरा नगर वन दतुनि पहाड़ी पर बनाया जाएगा। इस बार 24 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है।

डीएफओ लाल सुधाकर सिंह का कहना है कि सिर्फ पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पानी की व्यवस्था करना भी जरूरी है, क्योंकि इन दिनों शहर में जल संकट की स्थिति बनी थी। इसलिए इस बार जंगलों में जल संरचनाएं बनने से बरसात का पानी जमीन में पहुंचेगा, जिससे भू-जल स्तर सुधरेगा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

इंदौर के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, जल संरक्षण के लिए हुई देश की सबसे छोटी रन मिनी थान

इंदौर। वर्षा जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से नगर निगम ने रविवार को पलासिया चौराहा से इंद्रप्रस्थ चौराहा तक लगभग एक किलोमीटर लंबी इंदौर की सबसे छोटी रन 'मिनी थान' आयोजित की। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया।

जन भागीदारी से सुधरेगा भूजल स्तर- सांसद- कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद शंकर लालवानी, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल एवं स्वास्थ्य प्रभारी अश्विनी शुक्ल ने किया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को वर्षा जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर जन भागीदारी का मॉडल है। हम सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाएं तो निश्चित ही इंदौर के भूजल स्तर में सुधार होगा।

नागरिकों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की अपील- निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा कि जल संकट की संभावित चुनौतियों को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को वर्षा जल संग्रहण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने नागरिकों से अपने घरों, संस्थानों एवं व्यावसायिक परिसरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं रिचार्ज पिट स्थापित करने की अपील की।

जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान- निगमायुक्त ने कहा कि इंदौर जनभागीदारी के लिए देश में प्रसिद्ध है और इसी जनसहभागिता की शक्ति के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। अगर प्रत्येक नागरिक इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे तो शहर के भूजल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है।

क्राइम ब्रांच का एक्शन, महालक्ष्मी नगर के कैफे पर आधी रात छापा, जुआ खेलते 32 गिरफ्तार

इंदौर। अपराध शाखा ने शनिवार रात एक कैफे पर छापा मारा। इसमें स्नूकर की आड़ में जुआ खिलाया जा रहा था। लसूड़िया पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। रातभर कैफे चलता था। बाहर वाहनों की कतारें लगी रहती थीं। देवास, शाजापुर से भी जुआरी आते-जाते थे। संचालक मौके से फरार हो गया है।

क्राइम ब्रांच की टीम ने ग्राहक बनकर की रैकी- डीसीपी (अपराध) राजेश त्रिपाठी के अनुसार रात करीब तीन बजे महालक्ष्मी नगर में दबिश दी गई है। सूचना मिली थी कि एक कैफे की आड़ में जुए का अड्डा संचालित हो रहा है। पुलिसकर्मियों ने ग्राहक बनकर रैकी की और इशारा मिलते ही दबिश दे दी।

मौके से 32 आरोपित गिरफ्तार, 1.42 लाख रुपये बरामद- मौके से आरोपित आशिक खान, कृष्णा जादौन, राजेश केथवास, सुनील सिंह, हेमराज सिंह, लक्ष्मीनारायण, हर्षित द्विवेदी, नीरज ठाकुर, कुलदीप मिश्रा, आसिफ मोहम्मद, कृष्णकुमार शर्मा, लाखन राजपूत, सतीश सोनी, धर्मेंद्र, विजय कुशवाह, मोहिल येले, सुधीर कुमार दुबे, सुशील जायसवाल, सुशील कुमार वर्मा, साजिद इब्राहिम, जितेंद्र पटेल, महेश मंजूलाल, जितेंद्र गुप्ता, प्रकाश गायकवाड़, राज बरुआ, कमलजीत, जीतू खोपड़े, जितेश राठौर, ऋषि नायडू, आरिफ मुबारिक सहित 32 को पकड़ लिया।

व्यापारियों और पुलिसकर्मियों के बेटे हैं आरोपित, संचालक फरार- पुलिस को मौके से 1 लाख 42 हजार रुपये मिले हैं। आरोपित व्यापारी, दुकानदार और पुलिसकर्मियों के बेटे हैं। संचालक पराग सिंह रघुवंशी है, जो मौके से फरार हो गया। इसके पूर्व भी क्राइम ब्रांच ने लसूड़िया क्षेत्र की पॉश कालोनी में दबिश देकर क्रिकेट का सट्टा पकड़ा था।

ग्लोबल विंड डे पर म.प्र. को मिला उभरती नवकरणीय ऊर्जा अवसंरचना उत्कृष्टता सम्मान

भोपाल। केन्द्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने आज गोवा में ग्लोबल विंड डे 2026 पर पवन ऊर्जा- महत्वाकांक्षा से तीव्र क्रियान्वयन तक विषय पर आयोजित सम्मेलन में मध्यप्रदेश को उभरती नवकरणीय ऊर्जा अवसंरचना उत्कृष्टता सम्मान प्रदान किया। इस सम्मान को मध्यप्रदेश के ऊर्जा सचिव श्री विशेष गढ़पाले ने ग्रहण किया। इस अवसर पर केन्द्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक सहित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राज्य नोडल एजेंसियों, डिस्कॉम्स, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, पवन टर्बाइन निर्माताओं, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, डेवलपर्स तथा अन्य पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस सम्मेलन को केन्द्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, गोवा ऊर्जा विकास एजेंसी के सहयोग और इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, विंड इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन तथा इंडियन विंड पॉवर एसोसिएशन के समर्थन से आयोजित किया गया।

सम्मेलन का उद्देश्य अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करना, प्रमुख हितधारकों के बीच प्राथमिकताओं का समन्वय करना तथा भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रिया के एक रणनीतिक स्तंभ के रूप में पवन ऊर्जा के विकास के अगले चरण पर विचार-विमर्श करना है।

सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने, आर्थिक विकास को समर्थन देने व विभिन्न क्षेत्रों में हरित रोजगार सृजन में पवन ऊर्जा की भूमिका पर भी चर्चा की गई।

ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूलों में लौटेगी रौनक, दोस्तों से मिलेंगे विद्यार्थी, जुटेंगे पढ़ाई में

भोपाल। प्रदेश भर के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 16 जून से विद्यालयों में फिर से रौनक लौटेगी। विद्यार्थी अपने मित्रों और शिक्षकों से मिलेंगे तथा नए उत्साह के साथ शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागी बनेंगे। इस अवसर पर समस्त शासकीय विद्यालयों एवं सांदीपनि विद्यालयों में 16 से 30 जून 2026 तक स्कूल चलें हम अभियान के द्वितीय चरण अंतर्गत शाला प्रारंभ उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से 8वीं तक की समस्त स्कूलों में बाल सभा के आयोजन के साथ ही पहले दिन विशेष भोज का आयोजन होगा। इसके साथ ही शाला में शत-प्रतिशत नामांकन, पुस्तक वितरण, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, क्रियाशील बालिका शौचालयों की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, अभिभावकों का शाला से जुड़ाव जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 16 जून से शुरू हो रहे नवीन शिक्षण सत्र को लेकर तैयारी भी पूरी कर ली है।

हर बच्चे को स्कूल भेजने का लक्ष्य- शाला में शत-प्रतिशत नामांकन के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कर प्रत्येक पात्र बच्चे को विद्यालय से जोड़े जाने का लक्ष्य है। इसके लिए ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की सूची तैयार कर मैदानी अधिकारियों एवं शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई है। जारी निर्देशों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य तथा संकुल प्राचार्य जिला स्तर पर नियमित समीक्षा करेंगे और विद्यालयवार प्रगति सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश का कोई भी बच्चा स्कूली शिक्षा से वंचित न रहे तथा सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित हो।

इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हमारे शिक्षक ऐप में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के अंतर्गत प्रमोशन पेंडिंग स्टूडेंट (2025-26 से 2026-27) मॉड्यूल विकसित किया गया है। इस मॉड्यूल में एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर कक्षोन्नति के लिए शेष विद्यार्थियों की सूची संबंधित विद्यालय के शिक्षकों के लॉगिन में प्रदर्शित की गई है। इन सभी छात्रों की कक्षोन्नति की जवाबदारी संबंधित शिक्षकों को सौंपी गई है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण के लिए विभाग ने मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। संबंधित पोर्टल पर पाठ्यपुस्तक निगम के डिपो से बीआरसीसी, बीआरसीसी से शाला एवं शाला से छात्र स्तर तक पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जाकर इंट्री सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ्यपुस्तक वितरित कर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर समय-बद्ध ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए।

प्राथमिक स्तर पर सीखने के स्तर में सुधार के लिए राज्य के निर्देशानुसार मैदानी स्तर मिशन अंकुर अंतर्गत विशेष कार्ययोजना तैयार कर एवं एफएलएन सर्वे 2025 के आधार पर बच्चों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा।

विद्यार्थियों की सुविधा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र ने मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि, शाला प्रारंभ होने पर सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, क्रियाशील बालिका शौचालय, रनिंग वॉटर की उपलब्धता, पानी की टंकी की साफ सफाई, आवश्यक मरम्मत एवं जन उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

जीत के पास पहुंचकर चुकी नीदरलैंड, आखिरी समय में जापान के कामदा ने बचाया ड्रॉ

नई दिल्ली (एजेंसी)। डलास स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का 10वां मैच नीदरलैंड और जापान के बीच खेला गया। दोनों टीमों के बीच खेला गया ये हाई-वोल्टेज मैच 2-2 की बराबरी पर छूटा।

डच टीम ने दो बार मैच में लीड बनाकर जीत की तरफ कदम बढ़ाए थे, लेकिन जापान के इरादे कुछ औप थे। दोनों बार पिछड़ने के बाद उन्होंने पलटवार करते हुए मैच से एक 1 अंक चुरा लिया। जापान के लिए 88वें मिनट में दाइची कामदा संकटमोचक बने, जिनका गोल मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ।

पहले हाफ तक 0-0 की बराबरी पर रही टीमें नीदरलैंड बनाम जापान के इस मैच में शुरुआत से ही नीदरलैंड ने गेंद पर कब्जा बनाए रखा और आक्रामक रुख अपनाया। डोनियल मालेन को गोल करने के लिए दो सुनहरे मौके मिले, लेकिन जापान के गोलकीपर जियोन सुजुकी ने शानदार तरीके से बचाव किया और नीदरलैंड को बढ़त नहीं लेने का मौका दिया। उन्होंने काउंटर-अटैक पर भरोसा दिखाया। पहले 45 मिनट में दोनों टीमें गोल नहीं कर पाई और हाफ टाइम तक स्कोर 0-0 की बराबरी पर रहा।

दूसरे हाफ में डच टीम ने बनाई लीड- दूसरे हाफ की शुरुआत के 5 मिनट बाद नीदरलैंड ने 1-0 की बढ़त हासिल की। टीम के लिए 50वें मिनट में रयान ग्रावेनबेर्ख की फ्री-किक पर कप्तान वर्जिल वैन डाइक ने शानदार हेडर लगाकर टीम को लीड दिलाई।

जापान का पलटवार- 0-1 से पिछड़ने के बाद जापान की टीम ने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया। 7 मिनट बाद यानी 57वें मिनट में ताकेफुसा कुबो ने बॉक्स के अंदर एक जादुई मूव बनाया और गेंद केइतो नाकामुरा की तरफ बढ़ा दी। नाकामुरा ने बिना कोई गलती मौके का फायदा उठाया और गेंद को सीधे नेटपोस्ट में पहुंचाया और इस तरह स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।

समरविल का कर्लिंग मैजिक- जापान के पलटवार के बाद नीदरलैंड ने 7 मिनट बाद फिर बढ़त हासिल की। 64वें मिनट में रयान ग्रावेनबेर्ख ने अपना दूसरा असिस्ट दर्ज कराया। उनके पास पर क्रिसेंसियो समरविल ने बॉक्स के बाहर से शानदार कर्लिंग शॉट लगाया, जिसे रोकने से जापानी गोलकीपर चूक गए। इस गोल के साथ नीदरलैंड ने 2-1 से बढ़त बना ली।

कामदा ने आखिरी समय में पलटी बाजी- मैच जब खत्म होने वाला था और डच खेमा जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, तभी 88वें मिनट में जापान को एक कॉर्नर मिला। कॉर्नर किक पर कोकी ओगावा के शॉट के बाद गेंद दाइची कामदा के पास पहुंची। कामदा ने तुरंत शॉट लगाया, जो डच डिफेंडर से टकराकर होते हुए गोलपोस्ट के अंदर चली गई।

इस गोल ने जापान को 2-2 से बराबरी दिला दी। इंजरी टाइम में दोनों ही टीमों ने विनिंग गोल के लिए कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली और मैच 2-2 की बराबरी पर छूटा। इस ड्रॉ के साथ नीदरलैंड और जापान ने 1-1 अंक हासिल किया।

दिल को रखना है चुस्त-दुरुस्त, तो इन तरह के फूड्स से आज ही बना लें दूरी

तला हुआ खाना- कई शोध से पता चला है कि सैचुरेटेड फैट्स शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। तले हुए खाने या फिर प्रोसेस्ड फूड्स में नमक और सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा काफी ज़्यादा होती है। दोनों दिल की सेहत पर काफी बुरा असर डालते हैं। रेड मीट, फ्रेंच फ्राइज़, सैंडविच, बर्गर आदि जैसे फूड्स ख्रु यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाते हैं, जिससे स्ट्रोक और दिल के दौरे का ख़तरा बढ़ जाता है।

चीनी युक्त सोडा या फिर केक- चीनी को मीठा ज़हर किसी वजह से ही कहा जाता है। केक, मफिन, कुकीज़ और मीठी ड्रिंक्स शरीर में सूजन का कारण बनते हैं। चीनी का ज़्यादा सेवन शरीर में फैट्स बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज़, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है।

लाल मांस- रेड मीट यानी मटन मांसाहारी लोगों के बीच काफी पॉपुलर होता है। हालांकि, यह सैचुरेटेड फैट्स से भरपूर होता है, जिसकी वजह से धमनियों में प्लाक जम सकता है।

जो लोगों को मटन खाने का शौक है, उन्हें वह हिस्सा खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा प्रोटीन और कम फैट हो।

अगर आप चिकन खा रहे हैं तो ब्रेस्ट, विंग्ज़ वाला हिस्सा में ज़्यादा प्रोटीन होता है और कम फैट। वहीं, मछली सबसे हेल्दी और अच्छा ऑप्शन है।

जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सेवन सेहत को पहुंचा सकता है नुकसान, ये होते हैं साइड इफेक्ट्स

जिस प्रकार शरीर के लिए मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिंस, फाइबर आदि जरूरी होते हैं वैसे ही प्रोटीन भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। लेकिन इन सब की भी एक निश्चित मात्रा तय होती है। अगर प्रोटीन की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाए तो ये आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं प्रोटीन की मात्रा शरीर में ज्यादा होने से व्यक्ति को किन समस्याओं का सामना कर पड़ सकता है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। मांसपेशियों के विकास के साथ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं प्रोटीन, हृदय व फेफड़े के ऊतकों को भी स्वस्थ रखते हुए शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। सेहत के लिए इतना फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सेवन आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

शरीर के लिए क्यों जरूरी है प्रोटीन- शरीर को 20 अलग-अलग अमीनो एसिड की जरूरत होती है। इन्हीं के माध्यम से शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन का उत्पादन होता है।

टेस्टी और हेल्दी खजूर तिल की चिक्की

इस चिक्की का सेवन ज्यादातर सर्दियों में किया जाता है। खजूर पौष्टिकता से भरपूर होने के साथ तासीर में भी थोड़ी गर्म होती है। ये न सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है बल्कि आपके शरीर को भी गर्म रखने में आपकी मदद करती है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है खजूर तिल की चिक्की।

खजूर तिल की चिक्की बनाने के लिए सामग्री

-1/2- कप तिल
-1 कप-खजूर
-1/4 कप-काजू (चॉप किए हुए)
-1/2 छोटा चम्मच - इलायची पाउडर
-2 चम्मच-घी
-चुटकी भर-सेंधा नमक
-1/4 कप- चीनी या गुड़
-1 कप - नारियल

खजूर तिल की चिक्की बनाने की विधि

खजूर तिल की चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी गर्म करके उसमें खजूर और गुड़ डालकर लगातार चलाते हुए पिघला लें। अब इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक इसी समय डालना है।

अब आप इसमें तिल डाल दें और इसे 30 सेकंड तक अच्छी तरह से पका लें। अब इसमें काजू, नारियल डालकर एक सेटिंग प्लेट में डालकर बराबर मात्रा में फैला लें ताकि गजक एक जैसी हो जाए।

अब इसे अपने मनचाहे शेप में काट लें और फिर 30 मिनट के लिए ठंडा होने दें। आपकी खजूर और तिल की चिक्की तैयार है। आप इस चिक्की को एयर टाइट कंटेनर में डालकर दो हफ्ते के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं।

शुभमन गिल का मास्टरप्लान! सीरीज जीतने के लिए करेंगे बड़े बदलाव रोहित पर टिकी निगाहें

नई दिल्ली (एजेंसी)। धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के साथ वनडे सीरीज का आगाज करने वाली भारतीय टीम बुधवार को होने वाले दूसरे वनडे को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। 3 वनडे मैचों की सीरीज का यह दूसरा मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

दूसरी और अफगान टीम की कोशिश सीरीज में वापसी करने पर होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि निर्णायक मैच में शुभमन गिल किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकते हैं।

रोहित को बनाने होंगे रन- वनडे विश्व कप 2027 में खेलने की बाट जोह रहे 39 साल के रोहित शर्मा को इस मैच में अपने आप को साबित करन होगा। पिछले मैच में वह 16 के स्कोर पर रन आउट हो गए थे। पिछले 5 वनडे में रोहित सिर्फ 1 अर्धशतक लगा पाए हैं।

ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ बचे हुए 2 वनडे उनके लिए किसी अवसर से कम नहीं हैं। दूसरी ओर कप्तान शुभमन गिल ने पिछले मैच में 66 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए थे। वह इस फॉर्म को जारी रखना चाहेंगी।

मिडिल ऑर्डर की बात करें तो इसमें ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल नजर आएंगे। राहुल ने पहले वनडे में 19 गेंदों पर 39 रन ठोक दिए थे। वह मैच की स्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आएंगे।

पिछले मैच में डेब्यू करने वाले स्पिनर हर्ष दुबे और तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट चटकाए थे।

दिवालिया पाकिस्तान की खुली पोल, एशियन गेम्स खेलने के लिए खिलाड़ी खुद उठाएंगे अपना खर्च

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान के शीर्ष पुरुष और महिला टेबल टेनिस खिलाड़ियों को उस समय बड़ा झटका लगा जब पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन (पीटीटीएफ) ने उनसे कहा कि इस वर्ष जापान में होने वाले एशियाई खेलों में अगर वे भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें अपनी यात्रा और अन्य खर्च स्वयं वहन करने होंगे।

लाहौर में ट्रॉयल्स- लाहौर में जारी दो दिवसीय राष्ट्रीय ट्रॉयल्स के दौरान जब कुछ खिलाड़ियों ने अपने दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते को लेकर महासंघ के अधिकारियों से जानकारी मांगी तब इस बारे में पता चला। एक खिलाड़ी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि हमें बताया गया है कि ट्रॉयल्स में हिस्सा लेने के लिए कोई भुगतान नहीं मिलेगा।

अनुदान नहीं मिला है

इसके अलावा, एशियाई खेलों के लिए चयनित खिलाड़ियों को अपने हवाई टिकट और खर्च के लिए प्रतिदिन 50 डॉलर की विदेशी मुद्रा स्वयं व्यवस्था करनी होगी। खिलाड़ी ने कहा कि जब खिलाड़ियों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई तो पीटीटीएफ एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें खुश होना चाहिए कि ट्रॉयल का आयोजन हो रहा है क्योंकि महासंघ को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड (पीएसबी) से कोई कोष या अनुदान नहीं मिला है।

कोई पदक नहीं जीता - इस खिलाडी ने कहा कि हमें बताया गया कि एशियाई खेलों के लिए भी पीटीटीएफ को पीएसबी से कोई अनुदान नहीं मिलता है। यह खेलों के विकास के लिए चिंताजनक स्थिति है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने अब तक एशियाई खेलों या एशियाई चैंपियनशिप में टेबल टेनिस में कोई पदक नहीं जीता है। इसका कारण मलेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे मजबूत देशों का दबदबा माना जाता है।

जर्मनी ने कुराकाओ से किया खिलवाड़, 7-1 से हराकर शुरू किया अपना अभियान

नई दिल्ली (एजेंसी)। अगर आपने कभी भी लुडविग वैन बीथोवेन, जोहान सेबेस्टियन बाख या रिचर्ड वैगनर का संगीत नहीं सुना तो फीफा विश्व कप 2026 के अपने पहले मैच में जर्मनी को खेलता देख लीजिए। इस खेल में सुर-लय-ताल के साथ बहुत सारा सुकून भी है। सुकून इस बात का कि 2014 के विश्व चैंपियन ने देर से ही सही, लेकिन इस सबसे बड़े मंच पर एक बार फिर से अपने खेल का जादू दिखाया।

दुनिया को बता दिया कि जब ये लय में होते हैं तो सुर और ताल खुद मैदान में हाजिरी लगाते हैं। पहली बार विश्व कप खेल रही कुराकाओ के लिए मैच की शुरुआत ही पिछले पांव पर हुई। मैच के छठे मिनट में ही फेलिक्स मेचा ने जर्मनी को बढ़त दिला दी और इस गोल में उनकी मदद की फ्लोरियन विर्त्ज ने। जर्मनी की टीम मैच की शुरुआत से ही कमाल की फुटबाल खेल रही थी जैसे उन्होंने तय कर लिया था कि कुराकाओ को पाठ पढ़ा देना है।

लिवानो कोमेनेंसिया का ऐतिहासिक कारनामा- जर्मनी ने बढ़त बनाने के बाद भी हमले जारी रखे लेकिन दूसरा गोल करने से पहले उन्हें एक झटका लगा। कुराकाओ के लिए लिवानो कोमेनेंसिया ने गोल मार दिया। वह फीफा विश्व कप में अपने देश के लिए गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। लोगों को लगा कि जर्मनी कहीं फिर से ना फिसल जाए लेकिन ये नई जर्मनी है, जो जहां जाती है वहीं मारती है।

संन्यास से लौटे मैनुएल नुएर ने गोल खाया तो जर्मन अटैकर्स ने अपने जलवे कई गुना बढ़ा दिए और एक के बाद एक चार गोल और मार दिए। शुरुआत डिफेंडर नीको श्लोटरबेक ने की जिन्होंने नथैनिएल ब्राउन के क्रास को हेडर के जरिए गोल में पहुंचाया।

पहले हाफ के अतिरिक्त समय में कुराकाओ के रीचेडली बजोर ने फेलिक्स नेमचा को पेनाल्टी एरिया में गिरा दिया, रेफरी ने तुरंत पेनाल्टी दे दी। काइ हावर्त्ज ने इसे गोल में बदल पहले हाफ की समाप्ति पर स्कोर 3-1 कर दिया। दूसरा हाफ शुरू होते ही जर्मनी ने जमाल मुसियाला के गोल के दम पर स्कोर 4-1 कर लिया।

काई हावर्त्ज ने दागा गोल- मुसिलाया ने कप्तान जोशुआ किमिख के पास को खूबसूरती के साथ गोल में धकेल फीफा विश्व कप 2026 में अपना खाता खोल लिया।

ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए डायबिटीज के मरीज अपनाएं ये आसान घरेलू नुस्खे

नई दिल्ली (एजेंसी)। अनियमित जीवनशैली और खानपान की गलत आदतों की वजह से होने वाली बीमारियों में डायबिटीज भी एक है। जल्दी थकान महसूस होना, अचानक वजन बढ़ना या घटना, भूख-प्यार ज्यादा लगना, बार-बार यूरिन आना, थोड़ी-थोड़ी देर में मुंह सूखना, धुंधला दिखना, व्यवहार में चिड़चिड़ापन आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर आप इससे जूझ रहे हैं, तो यहां दिए गए घरेलू उपचार आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

- हफ्ते में तीन दिन यानी हर दूसरे दिन एक करेले के रस में आधा नींबू, चुटकीभर काली मिर्च और स्वादानुसार नमक मिलाकर पीने से डायबिटीज से राहत मिलती है।
- हफ्ते में दो बार एक ग्लास गुनगुने पानी में आधा टीस्पून दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से डायबिटीज में आराम पहुंचता है।
- नियमित खाना खाने के बाद सौंफ खाने से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है।
- डायबिटीज होने पर शलजम का सैलेड खाना भी फायदेमंद होता है।
- सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ आधा टीस्पून अलसी के बीजों का पाउडर लेने से शुगर से राहत मिलती है।
- रातभर पानी में भीगे मेथी के दानों को सुबह चबा-चबाकर खाने और बचे हुए पानी को पीने से डायबिटीज परेशान नहीं करती।
- रातभर पानी में भीगे बादाम सुबह छीलकर खाने से डायबिटीज में फायदा पहुंचता है।
- रोज सुबह आधा कप व्हीट ग्रास का ताजा जूस पीने से डायबिटीज से राहत मिलती है।
- डायबिटीज होने पर जामुन पर नमक लगाकर खाने से आराम पहुंचता है। गुनगुने पानी के साथ जामुन की गुठली का पाउडर लेने से भी राहत मिलती है।
- दिन में दो बार 10 मिलीग्राम आंवले के रस में चुटकीभर हल्दी पाउडर मिलाकर लेने से डायबिटीज परेशान नहीं करती।
- सहजन के पत्तों के सेवन से डायबिटीज के रोगियों को लाभ होता है।
- सुबह खाली पेट नीम के पत्तों का जूस पीने से भी डायबिटीज में आराम मिलता है।
- अमरूद पर काला नमक छिड़क कर खाने से डायबिटीज में फायदा मिलता है।
- नियमित ग्रीन टी पीने से भी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है।
- रोज खाली पेट दो-तीन तुलसी के पत्तों के सेवन से डायबिटीज के खतरे को कम किया जा सकता है।
- बिना दूध और चीनी वाली कॉफी के सेवन से डायबिटीज से राहत मिलती है।

यदि आपके हाथ – पैरों में भी अकड़न आने लगी है, तो जानिए कैसे पाना है इससे छुटकारा

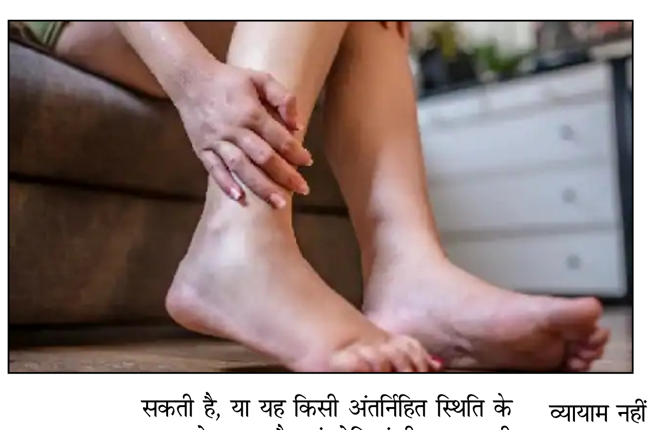

नई दिल्ली (एजेंसी)। आजकल मौसम में काफी ठंडक होने लगी है और सर्दियां पीक पर हैं। यही वजह है कि लोग अपने घरों से कम बाहर निकलते हैं। इसकी वजह से लोगों कि शारीरिक गतिविधि भी कम हो जाती है। यही वजह है कि लोगों की मासपेशियों में धीरे ङ्क धीरे अकड़न आने लगती है। यह सर्दियों में सभी को आने वाली एक समस्या है, जिक्सा इलाज करना बहुत ज़रूरी है।

मांसपेशियों में अकड़न की वजह से चलने ङ्क फिरने में तकलीफ होने लगती है। बड़े ङ्क बुजुर्गों के साथ यह समस्या ज्यादा आती है, क्योंकि उन्हें चलने में पहले से ही दिक्कत होती है। तो चलिए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि क्या है मसल्स में अकड़न के करण और इसके उपाय।

क्या होती है मांसपेशियों में अकड़न- मांसपेशियों की अकड़न अक्सर दर्द का कारण होती है। किसी विशेष मांसपेशी के ज्यादा उपयोग के बाद भी मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है, या यह किसी अंतर्निहित स्थिति के करण हो सकता है। मांसपेशियां तीन प्रकार की होती हैं- स्केलिटल, कार्डिएक और स्मूद।

मसल्स की जकड़न मुख्य रूप से स्केलिटल मांसपेशी को प्रभावित करती है, जो मनुष्य को दैनिक गतिविधियों को करने में सक्षम बनाती है। यदि कोई समस्या तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों की कोशिकाओं के बीच संचार में बाधा डालती है, तो मांसपेशियां सिकुड़ सकती हैं और इसके परिणामस्वरूप अकड़न हो सकती है।

मांसपेशियों में अकड़न का क्या कारण है- स्केलिटल मांसपेशियों के अत्यधिक उपयोग के बाद मांसपेशियों की जकड़न सबसे अधिक उत्पन्न होती है, जो कि गति की कमी या नए व्यायामों में इंगेज होने के बाद होती है। इन क्रियाओं से मांसपेशियों की कोशिकाओं को अस्थायी नुकसान हो सकता है, जिससे अकड़न हो सकती है। मसल्स के ज्यादा प्रयोग से मांसपेशियों की जकड़न अक्सर उन लोगों में होती है जो व्यायाम नहीं करते हैं।

इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन भी मांसपेशियों की कठोरता का कारण बन सकता है, खासकर व्यायाम के बाद। इलेक्ट्रोलाइट्स (जैसे, सोडियम, पोटेशियम, आदि) शरीर में महत्वपूर्ण खनिज हैं जो अन्य कार्यों के बीच तंत्रिका और मांसपेशियों को अनुबंधित करने में भूमिका निभाते हैं। जब कोई व्यक्ति व्यायाम करता है, तो पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स खो जाते हैं। जिससे तंत्रिका तंत्र के लिए मांसपेशियों की गति को सुविधाजनक बनाना अधिक कठिन हो जाता है।

इजरायल ने बेरूत पर किए ताबड़तोड़ हमले, ईरान ने चेताया; ट्रंप ने की शांति की अपील

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान समझौते को लेकर ईरान की प्रमुख शर्तों में लेबनान पर इजरायली हमलों को रोकना भी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि, एपी के अनुसार, इजरायल ने बेरूत पर हमले और तेज कर दिए हैं। लड़ाकू विमानों द्वारा किए गए हमलों में हिजबुल्ला का एक कमांडर मारा गया है।

इजरायल ने बेरूत पर किया हमला - सीएनएन के अनुसार, इजरायल ने इन अभियानों की जानकारी अमेरिका को भी दी है और ईरान की ओर से संभावित बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की आशंका को ध्यान में रखा है।

उधर, लेबनान ने इजरायल पर खतरनाक रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। अधिकारियों के अनुसार, ऐसे एक हमले में तीन सैनिकों की मौत हुई है। ईरानी सैन्य अधिकारी मोहम्मद जफर असादी ने कहा कि बेरूत पर इजरायली हमलों का जवाब दिया जाएगा। वहीं, ईरानी संसद अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि वह या तो अपने वादे निभाना नहीं चाहता या उन्हें पूरा करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि बेरूत के दाहियेह क्षेत्र पर हमला अमेरिका की विफलता को दर्शाता है।

ईरान की संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग ने भी जल्दबाजी में समझौता करने के प्रति आगाह किया है। आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने कहा कि इजरायल को नियंत्रित किए बिना किसी समझौते पर आगे बढ़ना नुकसानदेह साबित हो सकता है।

ट्रंप ने इजरायल को फिर दी चेतावनी- न्यूयॉर्क टाइम्स से अनुसार, बेरूत पर हमले को लेकर ट्रंप ने भी हस्तक्षेप किया और इजरायल को चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने को कहा है।

ट्रंप ने कहा कि ऐसे समय में बेरूत पर हमला नहीं होना चाहिए था जब अमेरिका और ईरान शांति समझौते के करीब हैं। इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन जिस हमले के जवाब में बेरूत पर हमला हुआ, वह बहुत छोटा और बेमतलब था, जिसमें कोई घायल या हताहत नहीं हुआ।

ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि ने की भारतीय नाविकों की हत्या की निंदा

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान के सर्वोच्च नेता के उप प्रतिनिधि मोहम्मद हुसैन जियाई निया ने रविवार को ओमान तट के पास जहाजों पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले में तीन भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान और विभिन्न देशों के जहाजों पर होने वाले हमलों को जल्द रोका जाएगा।कलमकार परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निया ने कहा, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि उपनिवेशवादी ताकतों के लाभ और हितों के कारण निर्दोष लोगों की जान जाए।

हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि हालात 28 फरवरी से पहले जैसे हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि ओमान तट के पास इस सप्ताह भारतीय चालक दल वाले तीन जहाजों पर हमला हुआ, जिनमें से बुधवार को हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई।

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गूगल CEO सुंदर पिचाई का विरोध, छात्रों ने लगाए फ्री फलस्तीन के नारे

नई दिल्ली (एजेंसी)। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2026 के ग्रेजुएशन समारोह के दौरान जब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई मंच पर आए तो लगभग 200 छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और हूटिंग की।

जैसे ही पिचाई का परिचय कराया गया छात्र अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। उन्होंने फलस्तीनी झंडे लहराए, सीटियां बजाई और विरोध में नारे लगाए। कई छात्र फलस्तीनियों के समर्थन में पारंपरिक स्कार्फ केफिया पहने हुए भी दिखे।

छात्रों ने पिचाई के भाषण के दौरान की हूटिंग - समारोह के वीडियो में छात्र ग्रेजुएशन गाउन और कैप पहने स्टेडियम से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। बाहर निकलते समय कुछ छात्रों की हूटिंग की आवाज भी सुनाई दी, जबकि स्टैनफोर्ड के पूर्व छात्र पिचाई अपना भाषण देते रहे।

पिचाई को यह कहते हुए सुना जा सकता है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह मेरे द्वारा दिया गया केवल दूसरा दीक्षांत भाषण है। पहला भाषण तो सचमुच मेरे घर के बैकयार्ड में ही हुआ था।

क्यों किया गया विरोध प्रदर्शन- यह वॉकआउट स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन फलस्तीन और नो टेक फॉर अपार्थाइड ने गूगल के आईडीएफ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और आईसीई के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स के विरोध में आयोजित किया था।

यह विरोध प्रदर्शन प्रोजेक्ट निंबस से जुड़ा था, जो गूगल और इजरायली सरकार के बीच 1.2 अरब डॉलर की क्लाउड-कंप्यूटिंग डील है। फलस्तीन-समर्थक कार्यकर्ताओं ने इस डील की आलोचना की है और गूगल पर अपनी टेक्नोलॉजी सेवाओं के जरिए इजरायल का समर्थन करने का आरोप लगाया है।

पिछले महीने हार्ड फोर्क नाम के टेक पॉडकास्ट पर पिचाई से पूछा गया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण के दौरान छात्रों की तरफ से होने वाली संभावित हूटिंग या विरोध का सामना वे कैसे करेंगे।

इस पर पिचाई ने कहा कि उन्हें युवाओं और उनके भविष्य पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि जो छात्र एआई की आलोचना करते हैं, वे भी आने वाले सालों में इस टेक्नोलॉजी के विकास की दिशा तय करने में मदद करेंगे।

एलन मस्क की कंपनी में वेल्डिंग करने वाला बना करोड़पति, स्पेसएक्स के आईपीओ से चमकी कर्मचारी की किस्मत

नई दिल्ली (एजेंसी)। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के शेयर बाजार में ऐतिहासिक डेब्यू ने कंपनी के हजारों कर्मचारियों की जिंदगी बदल दी है। कर्मचारी शेयर ओनरशिप की वजह से कंपनी में काम करने वाले एक साधारण पूर्व वेल्डर, जुआन हर्नांडेज, आज करोड़पति बन चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जुआन हर्नांडेज ने साल 2015 में एक दोस्त के कहने पर स्पेसएक्स में बतौर वेल्डर काम शुरू किया था। उस समय उन्हें कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और वे इसे सिर्फ एक आम कॉन्ट्रैक्ट जॉब की तरह देख रहे थे।

75 अरब डॉलर के IPO ने चमकाई किस्मत- स्पेसएक्स ने हाल ही में शेयर बाजार में कदम रखते हुए अब तक का सबसे बड़ा लगभग 7.13 लाख करोड़ रुपये का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पूरा किया। जुआन हर्नांडेज ने ब्लू ओरिजिन कंपनी में जाने से पहले स्पेसएक्स में लगभग 10 साल काम किया था।इस दौरान उन्हें कंपनी की तरफ से शेयर मिले थे और आज उनके पास स्पेसएक्स के लगभग 6,500 शेयर्स हैं। बाजार में एंट्री के बाद स्पेसएक्स का एक शेयर लगभग 15,308 रुपये पर बंद हुआ। इस हिसाब से हर्नांडेज के शेयरों की कीमत लगभग 9.95 करोड़ रुपये हो चुकी है।

शुरुआत में नहीं दिया था ध्यान - हर्नांडेज ने बताया कि जब 2015 में उन्हें नौकरी पर रखा गया था, तब कंपनी ने उन्हें लगभग करीब 9.5 लाख रुपये के शेयर ऑफर किए थे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में मैंने इस ऑफर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इससे पहले मुझे किसी भी नौकरी में कंपनी के शेयर्स नहीं मिले थे।

स्पेसएक्स में अपने सफर के दौरान हर्नांडेज ने लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद की और बाद में वे एक सुपरवाइजर के पद तक पहुंचे। उनका मानना है कि जब कर्मचारियों को कंपनी में हिस्सेदारी (शेयर) मिलती है, तो उनमें जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है, क्योंकि वे सीधे कंपनी की सफलता से जुड़ जाते हैं।

बच्चों को सिखाएंगे निवेश के गुर- करोड़पति बनने के बाद भी हर्नांडेज के पैर जमीन पर हैं। उन्होंने कहा कि उनका काम रोकने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय, वे इस पैसे का इस्तेमाल अपने बच्चों को निवेश और लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाने के लिए करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी टीनएज बेटी को अभी से शेयर बाजार के बारे में सीखना शुरू करने के लिए प्रेरित किया है।

स्पेसएक्स के IPO ने रचा इतिहास- गौरकतलब है कि नास्डैक पर स्पेसएक्स की इस धमाकेदार लिस्टिंग ने इतिहास का सबसे बड़ा IPO होने का गौरव हासिल किया है। इस लिस्टिंग से जहां एक तरफ कंपनी के मालिक एलोन मस्क की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी में काम करने वाले हजारों आम कर्मचारी भी रातों-रात करोड़पति बन गए हैं।

ट्रंप टैरिफ धरा रह गया! अमेरिका को आखिरकार लौटाने ही पड़े भारत के 94649000000 रुपये, रिफंड प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली (एजेंसी)। एक समय था जब हर दिन ट्रंप टैरिफ की चर्चा होती थी। हर दिन नए टैरिफ से भारतीय लोग परेशान और हैरान रहते थे। हालांकि अब राहत की खबर आने लगी है। टैरिफ का सीधा असर भारतीय एक्सपोर्टर्स पर पड़ रहा था। ऐसे में उनके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। अमेरिका ट्रंप टैरिफ के तौर पर जमा किए गए 10 अरब डॉलर (लगभग 94,649 करोड़) से ज्यादा की रकम वापस कर रहा है। US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के प्रशासनिक निर्देशों और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों में ढील के बाद, इतनी बड़ी रकम वापस करने की प्रक्रिया अब तेजी पकड़ रही है।

क्यों और कैसे फंसा था यह पैसा- यह पूरा मामला अप्रैल 2025 में शुरू हुआ, जब अमेरिका ने उन देशों पर जुर्माना लगाने के लिए एक कड़ा व्यापार कानून लागू किया जिनका अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) था। इस कानून के तहत, 7 अगस्त 2025 को भारत पर 25त्न का टैरिफ लगाया गया और इसके बाद 27 अगस्त 2025 को रूस से कच्चे तेल के आयात को लेकर अतिरिक्त 25त्न का जुर्माना लगाया गया।

इन दोहरे लेवी (टैक्स) की वजह से, भारत के मुख्य एक्सपोर्ट उत्पादों जैसे टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग का सामान, लेदर और ज्वेलरी पर 50त्न का भारी कुल टैक्स बोझ पड़ा। हालांकि, 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इन लेवी को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिससे इनके रिफंड का रास्ता साफ हो गया। यह रकम अगस्त 2025 और फरवरी 2026 के बीच किए गए एक्सपोर्ट के लिए देय है।

बिज़नेस लाइन अखबार की रिपोर्ट में बताए गए सूत्रों के अनुसार, खातों में छोटी रकम आनी शुरू हो गई है, हालांकि बड़ी रकम आने में कुछ समय लगेगा। डिजिटल पेमेंट गेटवे ने भी इस प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए कदम उठाए हैं और बहुत कम लागत पर रिफंड ट्रांसफर की सुविधा दे रहे हैं।

अनिल अग्रवाल की एक और कंपनी करेगी शेयर बाजार में एंट्री? अरबपति ने खुद खोला राज

नई दिल्ली (एजेंसी)। वेदांता से अलग हुई चारों कंपनियों की लिस्टिंग हो गई। इस बीच वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सोमवार को ग्रुप की पैरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को विदेश में फिर से लिस्ट करने का संकेत देते हुए कहा कि ऐसा करने की तत्काल कोई योजना नहीं है और इसमें लगभग तीन साल लग सकते हैं। अग्रवाल ने कहा कि वेदांता रिसोर्सेज को विदेशी बाजार में दोबारा लिस्ट किए जाने के सवाल पर कहा, ÷अभी यह प्राथमिकता में नहीं है, लेकिन भविष्य में अमेरिका या किसी अन्य बाजार में इसे दोबारा लिस्ट करने से उल्लेखनीय वैल्यू क्रिएट की जा सकती है।

अनिल अग्रवाल का लॉन्ग टर्म प्लान- वेदांता रिसोर्सेज को लंदन स्टॉक एक्सचेंज से अनलिस्ट किया जा चुका है। कंपनी वहां पर एफटीएसई 100 सूचकांक में शामिल थी। अग्रवाल ने कहा कि वेदांता ग्रुप का राजस्व इस समय 23-24 अरब डॉलर है, जिसे बढ़ाकर 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि ग्रुप का लक्ष्य धातु, खनन, तेल एवं गैस, बिजली और महत्वपूर्ण खनिज जैसे अपने महत्वपूर्ण कारोबार का विस्तार करते हुए प्रत्येक क्षेत्र को लॉन्ग टर्म में 100 अरब डॉलर के अवसर में बदलना है।

लिस्ट हो गई चारों कंपनियां- इस बीच, वेदांता ग्रुप की चार अलग-अलग यूनिट्स (वेदांता एल्युमिनियम मेटल, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील) सोमवार को शेयर बाजार में लिस्ट हो गईं। भारतीय बाजार में कारोबार करने वाली वेदांता लिमिटेड के विभिन्न कारोबार को अलग-अलग इकाइयों के रूप में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दिसंबर, 2025 में मुहर लगाई थी।

वेदांता लिमिटेड ने यह फैसला अलग-अलग क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र व्यवसाय खड़ा करने और वृद्धि अवसरों का फायदा उठाने के लिए किया है। अग्रवाल ने कहा कि कंपनी भारत में बढ़ती धातुओं और ऊर्जा की मांग को देखते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है।

तेल उत्पादन पर रहेगा फोकस- एल्युमिनियम खपत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति खपत केवल तीन किलोग्राम है, जबकि वैश्विक औसत 30-40 किलोग्राम है, जिससे इसमें वृद्धि की बड़ी संभावना है। तेल एवं गैस क्षेत्र में उन्होंने कहा कि कंपनी ने ऐसे भंडार चिह्नित किए हैं, जिनसे अगले तीन वर्षों में उत्पादन बढ़ाकर पांच लाख बैरल प्रतिदिन किया जा सकता है।

इस्पात क्षेत्र में कंपनी 1.5 करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। अग्रवाल ने दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का जिक्र करते हुए कहा कि भविष्य में कंपनी की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 20-25 प्रतिशत हिस्सा परमाणु ऊर्जा से आ सकता है।

अमेरिका-ईरान डील से शेयर बाजार में गजब उछाल, 736 अंक उछलकर Sensex हुआ बंद

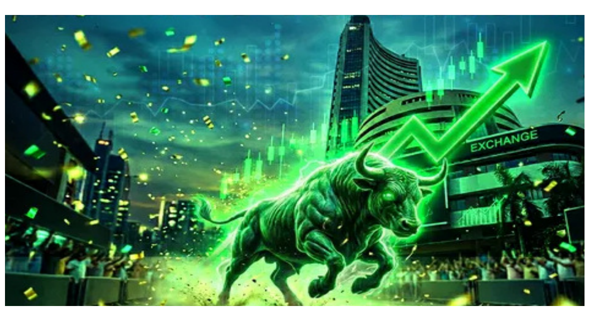

नई दिल्ली (एजेंसी)। सोमवार को वैश्विक बाजारों में तेजी और अमेरिका और ईरान द्वारा 107 दिनों के युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप देने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के चलते बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल आया।

सेंसेक्स 736.38 अंक या 0.97 प्रतिशत बढ़कर 76,264.33 पर बंद हुआ। वहीं, व्यापक बाजार निफ्टी 231 अंक या 0.98 प्रतिशत चढ़कर 23,853.90 पर पहुंच गया।

एनएसई पर सभी क्षेत्रीय सूचकांक हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। व्यापक सूचकांक निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी मिडकैप 100 में क्रमशः 1.62 प्रतिशत और 1.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

अंतरिम अमेरिका-ईरान शांति समझौते ने बढ़ाई निवेशक भावना- अंतरिम अमेरिका-ईरान शांति समझौते ने निवेशक भावना को काफी बेहतर कर दिया है, जिससे इक्विटी बाजारों में व्यापक रिकवरी देखने को मिली है। क्रूड ऑयल की कीमतें 85 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आने से महंगाई की चिंताएं कम हुई हैं। इससे ब्याज दरों का आउटलुक स्थिर हुआ है और FY27 के लिए कमाई की दृश्यता बढ़ी है। जैसा कि इक्विटी के लिए रिस्क-रिवार्ड समीकरण अनुकूल हो रहा है, निवेशक अब ग्रोथ-उन्मुख सेक्टरों जैसे ऑटो, इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट की ओर रुख कर रहे हैं। ये सेक्टर बेहतर मैक्रो वातावरण से फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। भू-राजनीतिक जोखिमों में कमी आने से बॉन्ड यील्ड्स में नरमी, FII आउटफ्लो में कमी और रुपए में मजबूती आने की उम्मीद है, जो बाजार की सकारात्मक आउटलुक को और मजबूत करेगी।- विनोद नायर, हेड ऑफ रिसर्च, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस - निफ्टी ने सोमवार को पश्चिम एशिया संघर्ष में कमी और अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर एग्रीमेंट की पृष्ठभूमि में शानदार ब्रेकआउट देखा और दिन के अंत में 231 अंक की मजबूती के साथ बंद हुआ।

बाजार 362 अंकों के बड़े अपसाइड गैप के साथ खुला, लेकिन पूरे सत्र में रेंजबाउंड कारोबार करता रहा। ओपनिंग अपसाइड गैप आंशिक रूप से भरा गया।डेली चार्ट पर गैप अप ओपनिंग के साथ एक छोटी लाल मोमबत्ती बनी, जिसने डाउन स्लोपिंग ट्रेंडलाइन के प्रमुख रेजिस्टेंस 23,750 को ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया।

क्या आप भी कर रहे हैं PF पर 8.25% ब्याज का इंतजार? आखिर कब खाते में आएगा पैसा?

नई दिल्ली (एजेंसी)। अगर आप भी अपने क्क्न खाते में 8.25त्न ब्याज का इंतजार कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। 2026-27 वित्त वर्ष शुरू हो चुका है, लेकिन लाखों श्वक्क्न सब्सक्राइबर्स के खातों में अभी तक ब्याज के पैसे की झलक तक नहीं दिखी है। अब ऐसे में सभी के मन में सवाल यही है कि पैसा कब आएगा और क्या देरी से आपका नुकसान हो सकता है?

क्या है पूरा मामला- Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25त्न ब्याज दर बरकरार रखी है, जो लगातार दूसरे साल वैसी की वैसी है उसे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्याज घोषित होने के बावजूद यह तुरंत खाते में नहीं आता और इससे जुड़े प्रोसेस में वक्त लगता है।

कब-तक आएगा ब्याज का पैसा- आमतौर पर EPF ब्याज सरकार की मंजूरी के बाद ही खातों में जमा होता है। पिछले ट्रेंड देखें तो ब्याज का पैसा जून से अगस्त के बीच में क्रेडिट हो सकता है और कुछ मामलों में यह सिंतबर तक भी जा सकता है।

यानी अभी जो देरी हो रही है वह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं आपके ब्याज के पैसे समय से खाते में आ जाएंगे।

ब्याज जुड़ता कैसे है- EPF पर ब्याज हर महीने कैलकुलेट होता है।

लेकिन इसे साल के अंत (31 मार्च) पर जोड़कर दिखाया जाता है।

इसके बाद EPFO सिस्टम अपडेट होने में कुछ महीने लग जाते हैं।

किस दर से ब्याज का पैसा आएगा- आपको बता दें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च के पहले सप्ताह में ब्याज दरों की घोषणा करते हुए कहा था कि EPFO वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% की ब्याज दर बनाए रखेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF जमा राशि पर 8.25त्न की सालाना ब्याज दर देने की सिफारिश की थी। अब किसके PF खाते में कितना ब्याज जमा होगा यह पूरी तरह आपके PF खाते में जमा पैसों पर निर्भर करता है। अगर आपके पीएफ खाते में 15 लाख रुपये है तो ब्याज लाखों में हो सकती है। वहीं, अगर पीएफ खाते में पैसा कम है तो ब्याज कम हो सकती है। जब भी आपको क्क्न खाते में ब्याज का पैसा जमा होता तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उसका मैसेज या नोटिफिकेशन जरूर आता है।

मध्यप्रदेश (परोपकारी संस्थाओं के लिए) मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति के प्रस्ताव पर उप समिति गठित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। बैठक में मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन-कल्याण को बड़ी रफ्तार देते हुए कुल 24,200 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण सहित कुल 19,472 करोड़ 29 लाख रुपये का पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया गया। राज्य में विश्वस्तरीय सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने और परोपकारी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए %मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 लागू करने के प्रस्ताव पर मंत्रि-परिषद ने 5 सदस्यीय मंत्रि-मण्डल उप समिति का गठन किया है। समिति सभी संबंधित पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी।

मंत्रि-परिषद ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल पर चलाने का पायलट प्रोजेक्ट भी मंजूर किया गया। वन्य-प्राणी संरक्षण और संवेदनशील क्षेत्रों के 94 गांवों के विस्थापन व मुआवजे के लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि 2026-2031 के तहत 2 हजार 381 करोड़ 15 लाख रुपये आवंटित किए हैं। सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देते हुए जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक व आवासीय सुविधाओं के लिए 687 करोड़ रुपये और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से रेशम उत्पादन की विभिन्न योजनाओं के लिए 639 करोड़ 25 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

मंत्रि-परिषद द्वारा श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन,औद्योगिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए 531 करोड़ 78 लाख रुपये तथा स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन व ऑडिट व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए स्थानीय निधि संपरीक्षा के संचालन के लिए 492 करोड़ 45 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह सभी निर्णय आगामी पांच वर्षों में मध्यप्रदेश के समग्र, समावेशी और सतत विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी पहल है।

इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की पुनरीक्षित लागत और अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 19 हजार 472 करोड़ 29 लाख रूपये की स्वीकृति- मंत्रि-परिषद ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की मूल लागत 7 हजार 500.80करोड़रूपये में 5 हजार 388.58 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत जोड़कर पुनरीक्षित लागत 12 हजार 889.38 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त उ?द्योग के स्वीकृत मानदंडों के अनुसार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण पीपीपी घटक एवं आंतरिक ऋष्ा के प्रभाव को सम्मिलित करते हुए 6 हजार 582.91 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस तरह कुल 19 हजार 472 करोड़ 29 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतिरिक्त वित्त पोषण में भारत शासन और मध्यप्रदेश शासन द्वारा 1,696 करोड़ 74 लाख रूपये की अतिरिक्त इक्विटी और केन्द्रीय करों के लिए 214 करोड़ 64 लाख रूपये का अतिरिक्त अधीनस्थ ऋष्ा, वित्त पोषण एजेंसी बैंकों से ऋष्ा निधि के विरुद्ध 3,496 करोड़ 15 लाख रूपये का अतिरिक्त पीटीए/आंतरिक ऋष्ा, मध्यप्रदेश शासन से राज्य करों के लिए 656 करोड़ 96 लाख रूपये एवं आईडीसीकी लागत के लिए 518 करोड़ 42 लाख रूपये का अतिरिक्त ऋष्ा शामिल है।

प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलिफेंट और ग्रामों के पुनर्वास संबंधी मुआवजा के लिए 2 हजार 381 करोड़ 15 लाख रूपये की स्वीकृति- मंत्रि-परिषद द्वारा वन विभाग के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलिफेंट और ग्रामों के पुनर्वास के लिए मुआवजा सम्बंधी योजना के सोलहवें केन्द्रीय वित आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक कुल 5 वर्षों तक संचालन के लिए कुल 2 हजार 381 करोड़ 15 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है।

स्वीकृति अनुसार प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलिफेंट (नॉन-रिकरिंग), प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलिफेंट (रिकरिंग) और प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलिफेंट (प्रोजेक्ट एलिफेंट) के लिए एक हजार 131 करोड़ 15 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन तीनों योजनाओं से वन्यप्राणी संरक्षण के वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर बनाई गई प्रबंध योजना का क्रियान्वयन किया जाना है, जिसमें मुख्यतः प्रदेश के टाइगर रिजर्व, कूनो राष्ट्रीय उद्यान तथा गांधीसागर अभयारण्य में वन एवं वन्य-प्राणी सुरक्षा के लिए हैबीटेट सुधार, अग्नि एवं वन सुरक्षा, जल स्त्रोतों का विकास, वन मार्गो का रखरखाव आवश्यक संरचनाओं का निर्माण एवं उनका रखरखाव, हाथियों का प्रबंधन एवं सुरक्षा कार्य, रेस्क्यू सामग्री क्रय, कैम्प निर्माण, दवाईयां क्रय एवं हाथियों के लिए भोजन व्यवस्था आदि कार्य किए जायेंगे। ग्रामों के पुनर्वास के लिए मुआवजा सम्बंधी योजना के लिए एक हजार 250 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है।

विश्व वरिष्ठजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों ने सौंपा ज्ञापन

देवास। विश्व वरिष्ठजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर देवास वरिष्ठ नागरिक संस्था के बैनर तले वरिष्ठजनों ने 15 जून को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर देवास को ज्ञापन सौंपकर वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों से अवगत कराया। संस्था अध्यक्ष ओ.पी. पाराशर ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार वरिष्ठजनों के साथ होने वाला शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक एवं सामाजिक दुर्व्यवहार मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

वरिष्ठजनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उनके सम्मानजनक जीवन की सुनिश्चितता के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 जून को अंतर्राष्टीय वरिष्ठजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ज्ञापन में मांग की गई कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी शासकीय कार्यालयों में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर सेवाएं प्रदान करने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को समाप्त कर पेंशनर्स को नियमित कर्मचारियों के समान समय पर महंगाई राहत का लाभ दिया जाए। वरिष्ठजनों ने आरोप लगाया कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद प्रदेश के पेंशनर्स को छठे वेतनमान का 32 माह तथा सातवें वेतनमान का 27 माह का एरियर भुगतान अब तक नहीं किया गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों के आर्थिक शोषण के समान है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन अधिकांश वरिष्ठजन इनकी जानकारी से वंचित हैं। इसलिए शासन स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है। संस्था ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 और मध्यप्रदेश नियम-2009 के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग करते हुए कहा कि वरिष्ठजनों की आर्थिक सुरक्षा, संपत्ति संरक्षण और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त पेंशनर्स को समय पर महंगाई राहत, केंद्र सरकार के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाएं, कैशलेस बीमा योजना में समान प्रीमियम, जिला स्तर पर पेंशन कार्यालयों की निरंतरता, सेवानिवृत्ति के साथ आयुष्मान सुविधा प्रारंभ करने तथा रेलवे किराए में वरिष्ठ नागरिकों को पूर्ववत छूट बहाल करने की मांग भी की गई। संस्था ने अंतर्राष्टीय वृद्धजन दिवस जैसे आयोजनों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता जताई।

ज्ञापन के माध्यम से वरिष्ठजनों ने शासन से उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। ज्ञापन का वाचन सचिव श्रवण कुमार कानूनगो ने किया एवं आभार सदस्य गंगासिंह सोलंकी ने माना। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष विपिन कुमार कुमावत, उपाध्यक्ष हिमांशु कुमार ढाली, संयुक्त सचिव बंशीधर चावड़ा, कार्यकारिणी सदस्य शीलनाथ आरस, मनोहर डी. सिन्हा, सुश्री वीणा भार्गव, के.सी. नागर, श्याम कुमार शाह, डॉ राजेंद्र सिंह ठाकुर, बाबूलाल मालवीय सतवास, सत्यनारायण वर्मा, अनिल नाईक सहित वरिष्ठ जन उपस्थित थे।

अपराधियों की धरपकड़ के लिए रातभर पुलिस ने की गश्त

शाजापुर। पुलिस ने रविवार-सोमवार की दरमियानी रात अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने रातभर कॉबिंग गश्त की और अपराधियों के ठिकानों पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया।

इसका उद्देश्य जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसना था। पुलिस अधीक्षक यशपालसिंह राजपूत के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय के नेतृत्व में जिलेभर के राजपत्रित अधिकारियों और थाना स्तर के 300 से अधिक पुलिसकर्मियों ने इसमें भाग लिया।

अभियान शुरू होने से पहले पुलिस अधीक्षक ने सभी टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस की अलग-अलग टीमें जिले के कई थाना क्षेत्रों में सक्रिय हुई। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी रातभर भ्रमण कर अभियान की निगरानी की। काम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने 47 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 78 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। अभियान के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 हजार रुपए के एक इनामी वारंटी को भी पकड़ा गया। पुलिस ने इस दौरान 12 जिला बदर अपराधियों का सत्यापन किया। इसके अलावा 73 गुंडा-बदमाशों और 104 निगरानीशुदा बदमाशों की भी जांच-पड़ताल की गई। आबकारी एक्ट के तहत पांच प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस ने 35 होटल, लॉज, ढाबों और धर्मशालाओं की सघन जांच की। बैंक, एटीएम और अन्य संवेदनशील स्थलों पर भी विशेष निगरानी रखी गई।

रिहा हुए कैदियों पर भी रखी नजर, संदिग्धों को भी तलाशा-पुलिस टीमों ने सक्रिय अपराधियों, जेल से रिहा हुए बदमाशों और संदिग्ध व्यक्तियों के घरों व संभावित ठिकानों पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। उन्हें आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी भी दी गई। यही नहीं पुलिस द्वारा इनकी आगामी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। एसपी यशपालसिंह राजपूत ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

हज से लौटे अशरफ मेव (गुड्डू) का गर्म जोशी के साथ स्वागत, कांग्रेस नेताओं ने गले लगाकर किया सम्मान

सिंगोली। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशरफ मेव (गुड्डू) के सोमवार को हज से लौटने पर कस्बे में जोरदार स्वागत किया गया।

इस दौरान परिजनों और रिश्तेदारों सहित विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाई तथा हज की मुबारक बाद देते हुए सकुशल वतन वापसी पर उन्हें बधाई दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात ट्रेन द्वारा मुंबई से रवाना होकर सुबह करीब 10 बजे वे कोटा पहुंचे तथा दोपहर साढ़े 12 बजे सिंगोली पहुंचे जहां पहले से मौजूद अंजुमन कमेटी के सदर डॉ. रईसुद्दीन कुरैशी, पूर्व सदर मोहम्मद जमील मेव सहित अंजुमन कमेटी के तमाम ओहदेदार और बड़ी संख्या में परिजनों और रिश्तेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। तत्पश्चात उन्हें बैंड बाजे और जुलूस के साथ घर लेजाया गया।

जुलूस के दौरान रास्ते भर जहां विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों ने उनका पुष्पहारों से स्वागत किया वहीं उन्होंने सभी को गले लगाकर उनके सभी के प्रति आत्मीयता व्यक्त की।

इस मौके पर पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजय तिवारी, पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश नागौरी, राजकुमार छिपा, राजेश बगड़िया, सुधीर लसोड़, धीरज मोटनाक, सहित भाजपा नगर अध्यक्ष लोकेश पटवा, भरत मोटानाक, मुकेश जैन, शीतल मेहता, राजकुमार व्यास, शंभुलाल शर्मा, पार्षद प्रतिनिधि संजय सुथार, नरेंद्र जायसवाल, कन्हैलाल जंगम सहित अन्य कई लोगों को साल श्रीफल के साथ अभिनंदन किया।

सिंगोली में कांग्रेस का मौन प्रहार: काली पट्टी बांध निकाला जुलूस, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

सिंगोली। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद सुश्री मिनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में सिंगोली कांग्रेस ने सोमवार को अनूठा प्रदर्शन किया।

ब्लॉक कांग्रेस, युथ कांग्रेस एवं नगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर गांधी भवन नया बस स्टैंड से तहसील कार्यालय तक पैदल मौन जुलूस निकाला। लोकतंत्र की हत्या के प्रतीक के रूप में काली पट्टी बांधे कार्यकर्ता बिना नारे लगाए शांतिपूर्ण तरीके से तहसील पहुंचे।

तहसील कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदार महोदय को राष्ट्पति श्रीमति द्रोपदी मुर्मु के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में प्रमुख आरोप- ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर विपक्षी प्रत्याशियों को चुनाव से बाहर रखा जा रहा है। मिनाक्षी नटराजन का नामांकन अत्यंत दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित होकर निरस्त किया गया, जो लोकतांत्रिक परम्पराओं की हत्या है।

1. विपक्षी प्रत्याशियों को सत्ता के दबाव में चुनाव से बाहर करने की प्रक्रिया पर रोक लगे।

2. मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो।

3. नामांकन निरस्त करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर को तुरंत निलंबित कर कानूनी कार्रवाई हो।

ज्ञापन सौंपने से पूर्व गांधी भवन पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए। मौन जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में कांग्रेस का झंडा था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है।

इस अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश सचिव सत्यनारायण पाटीदार, सिंगोली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सत्यनारायण धाकड़ ,रतनगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शंभू लाल चारण ,पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सौभागमाल नागौरी, जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष मनीष जैन, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश भंडारी ,जिला कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया प्रभारी राजकुमार छिपा ,मंडल अध्यक्ष रितेश सेठिया ,जिला युवा कांग्रेस सचिव राहुल जैन,पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बनवारी जोशी ,पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश नागोरी, पूर्व पार्षद जमील मेव,अल्पसंख्यक ब्लॉक अध्यक्ष इमरान खान, युवा कांग्रेस जावद विधानसभा अध्यक्ष सरवन सेन, एडवोकेट संजय नागोरी, ब्लॉक अध्यक्ष संदीप शर्मा ,विधानसभा सोशल मीडिया प्रभारी मानक धाकड़ , झांतला मंडल अध्यक्ष मानक जैन ,पूर्व मंडल अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ,पार्षद प्रतिनिधि सत्यनारायण बिश्नोई ,नानालाल धाकड़ ,इकबाल मंसूरी ,रामेश्वर झांतला, शंकर लाल धाकड़ ,धीरज जैन,अशोक छिपा, अरविंद जैन, प्रेमचंद छिपा ,अरविंद सोनी ,पीयूष नागोरी, आसिफ पठान, शाहिद मोहम्मद,ब्लॉक कांग्रेस ,नगर कांग्रेस ,यूथ कांग्रेस के कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।

अस्पताल ही परोस रहा बीमारियां, परिसर में लगा गंदे पानी का अंबार

शाजापुर। जिला अस्पताल के दवा वितरण केंद्र के बाहर गंदा पानी जमा होने से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिसर में फैली गंदगी के कारण बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों पर सवाल उठ रहे हैं।

एक ओर जहां जिला प्रशासन मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल परिसर में ही गंदे पानी का जमाव मच्छरों के पनपने का कारण बन रहा है। दवा वितरण केंद्र के बाहर पानी भरे रहने से आसपास का वातावरण दूषित हो गया है और तेज बदबू फैल रही है। हालात ये है कि लोगों का परिसर में खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि एक तरफ गंदे पानी की बदबू और दूसरी ओर मच्छरों का प्रकोप जिससे लोगों का बुरा हाल हो रहा है। जिला अस्पताल में दवा लेने आए एक मरीज ने बताया कि यहां काफी बदबू आ रही है। उन्होंने तत्काल साफ-सफाई कराने की मांग की, ताकि मरीजों को असुविधा न हो। युवक के अनुसार लोग बीमारी का इलाज कराने आते हैं, लेकिन ऐसी गंदगी से उन्हें नई बीमारियों का खतरा हो सकता है। इस मामले में सिविल सर्जन डॉ. बी.एस. मैना ने जानकारी दी कि कर्मचारियों को सफाई के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि एक पाइप टूट जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। डॉ. मैना ने आश्वासन दिया कि पाइप की मरम्मत कराकर जल्द ही पानी की निकासी और साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

चेतक की याद में दौड़ेंगे अश्व, तैयारियां पूर्ण

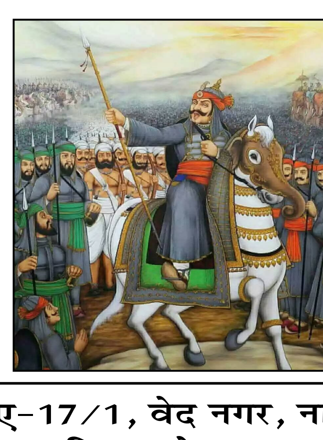

देवास। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी चेतक घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति के सदस्य धर्मेन्द्रसिंह बैस ने बताया कि संरक्षक विधायक गायत्रीराजे पवार के मार्गदर्शन में हल्दीघाटी युद्ध में भारत की आन-बान-शान के प्रतीक महान साहसी एवं फुर्तीले घोड़े चेतक को समर्पित यह प्रतियोगिता 17 जून को भोपाल बायपास स्थित सेंट्रल इंडिया स्कूल के सामने आयोजित होगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ दोपहर 2 बजे से किया जाएगा। धर्मेन्द्रसिंह बैस ने बताया कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार विजय पंडित की ओर से, द्वितीय पुरस्कार नवीनसिंह सोलंकी की ओर से प्रदान किया जाएगा। वहीं अन्य विजेताओं को वीरेन्द्र सिंह ठाकुर की ओर से शील्ड एवं मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह ठाकुर सरपंच पटलावदा की ओर से सभी प्रतिभागियों का सम्मान भी किया जाएगा।

मालिक, प्रकाशक, मुद्रक अशोक त्रिपाठी मो: 9425379389 द्वारा एमआईजी ए-17/1, वेद नगर, नानाखेडा, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित कर प्रियंका ऑफसेट, 2/10 पिपलीनाका, भैरुगढ रोड, उज्जैन (म.प्र.) से मुद्रित, सम्पादक : अभय नरवरिया मो: 9584111186 (सभी वाद-विवादों का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)